twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | बुधवार, 23 जुलाई, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 247, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर

उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर विपक्ष ने उठाए सवाल

बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर राजनीति करने वाले घबराए हुए हैं: रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली/एजेंसी

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के विरोध पर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अभियान से बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर राजनीति करने वाले नेता ही घबराए हुए हैं। भाजपा सांसद प्रसाद ने संसद भवन परिसर में मीडियाकर्मियों से कहा कि भारत के संविधान के मुताबिक सिर्फ.देश के निवासी को ही वोट देने का अधिकार है। अगर इसकी जांच हो रही है तो उन्हें दिक्कत क्यों है। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद सभी दलों को अपील करने का अधिकार है। वे अपील कर सकते हैं। न जाने क्यों विपक्षी दल इसको लेकर हाय तौबा मचाए हुए हैं। अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में 125 प्रतिशत लोगों को आधार कार्ड जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि ज्यादातर लोग बाहर से आए हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है।

भारत की सतत आर्थिक वृद्धि उसे वैश्विक स्थिरता का आधार बनाती है: बेरी

नई दिल्ली/एजेंसी

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने मंगलवार को कहा कि भारत की सतत आर्थिक वृद्धि उसे विश्व के लिए स्थिरता का आधार बनाती है जिसे वृद्धि के नए इंजनों और विकास मॉडलों की आवश्यकता है, जिन्हें बढ़ाया और साझा किया जा सके। बेरी ने कहा कि इस दिशा में भारत एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। सुमन बेरी ने एक्स पोस?ट में बताया कि सोमवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सतत विकास लक्ष्यों पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया को ऐसे नए विकास मॉडल और वृद्धि के नए इंजनों की आवश्यकता है, जिन्हें बड़े पैमाने पर अपनाया और साझा किया जा सके। उन्होंने कहा कि परिवर्तनशील युग में भारत एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। इसके सामाजिक-आर्थिक संकेतक निरंतर बेहतर हो रहे हैं।

नई दिल्ली/एजेंसी

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। यह जानकारी राज्यसभा में पीठासीन घनश्याम तिवाड़ी ने दी। धनखड़ सदन की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हुए। सुबह 11 बजे अपर सदन की कार्यवाही की शुरूआत जदयू सांसद हरिवंश ने की। इससे पहले खबर आई थी कि जगदीप इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। ना ही विदाई समारोह में शामिल होंगे। उधर, पीएम मोदी ने कहा कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। उन्होंने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा था, 'ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त, 2027 में रिटायर हो जाऊंगा।'

राष्ट्रपति को लिखे त्यागपत्र में धनखड़ ने पद छोड़ने की वजह स्वास्थ्य बताया था। विपक्ष इस्तीफे पर सवाल कर रहा है। कह रहा है कि इसकी वजह कुछ और है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को बताया, '21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की।

इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं आए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि धनखड़ को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने अगली बैठक दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए, जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया है।

जल्द से जल्द कराने होंगे उपचुनाव

उपराष्ट्रपति के पद छोड़ने के साथ ही राज्यसभा के सभापति पद भी स्वतः रिक्त हो गया। उपराष्ट्रपति उच्च सदन के पदेन सभापति होते हैं। ऐसे में अब जब इस्तीफा मंजूर हो गया है तो मानसून सत्र में राज्यसभा की पूरी कार्यवाही उपसभापति हरिवंश चलाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति की ओर से अधिकृत सदस्य को भी यह जिम्मेदारी दी सकती है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जल्द से जल्द कराना होता है। संविधान के अनुसार, मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने या अन्य किसी कारण से उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव यथाशीघ्र कराने का प्रावधान है। कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देने वाले धनखड़ तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। वीवी गिरि ने 20 जुलाई, 1969 और आर वेंटकरमन ने 24 जुलाई, 1987 को पद से इस्तीफा दिया था। दोनों ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए यह कदम उठाया था।

धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है

हमें इसका मान रखना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसके पीछे कुछ और गहरे कारण हैं। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। साथ ही, यह उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है, जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अजय माकन सोमवार को संसद परिसर में। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने इसे 'सोवियत स्टाइल इस्तीफा' बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में इस घटनाक्रम पर काफी कुछ सामने आएगा।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे धनखड़ का "व्यक्तिगत निर्णय" बताते हुए कहा कि भाजपा वोट कटवाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है।

विपक्ष ने की मानसून सत्र में पीएम की उपस्थिति की मांग, बताई प्राथमिकताएं

नई दिल्ली/एजेंसी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को बिहार में जारी मतदाता सूची अपडेट प्रक्रिया एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के मुद्दे पर संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। इममें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, द्रमुक और अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता थे। सभी ने अपने हाथ में एसआईआर के विरोध में पोस्टर कार्ड पकड़े हुए थे। इनमें लिखा था कि एसआईआर भारतीयों के अधिकार छीन रहा है। साथ ही इसे रोके जाने के नारे लगाए जा रहे थे। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर करा रहा है। इसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना है। इसमें 90.67 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने फार्म भरे हैं। इससे आगे ड्राफ्ट मतदाता सूची और 30 सितंबर तक अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी। विपक्षी दलों ने मंगलवार को संसद सत्र के लिए अपनी प्राथमिकताएं रखीं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद में स्वयं इसका जवाब देने की मांग की। इन मुद्दों में पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप का बयान तथा बिहार एसआईआर प्रक्रिया शामिल हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी साझा की।

आधार, मतदाता और राशन कार्ड केवल पहचान के लिए मान्य: चुनाव आयोग

नई दिल्ली/एजेंसी

बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने है। इसके लिए राज्यभर की राजनीति में गर्माहट तेज है। हालांकि गर्माहट का एक और बड़ा कारण चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2025) के फैसले को लेकर भी है। जहां विपक्षी दल लगातार से चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मंगलवार को चुनाव आयोग ने बिहार में चल रहे एआईआर-2025 को लेकर उठ रहे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सफाई दी है। अपने हलफनामें में चुनाव आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे अयोग्य व्यक्तियों को मतदाता सूची से हटाया जाता है। आयोग ने बताया कि एसआईआर-2025 के दौरान आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसी पहचान से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल केवल पहचान स्थापित करने के लिए किया जा रहा है, नागरिकता या निवास प्रमाण के रूप में नहीं।

आधार से पहचान, नागरिकता नहीं

आधार नंबर देना वैकल्पिक है और यह केवल पहचान के लिए लिया जा रहा है ना कि नागरिकता साबित करने के लिए।

आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अनुसार, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसके साथ ही आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत का कोई भी नागरिक तभी वोट डाल सकता है जब वह 18 साल का हो और सामान्य रूप से उस क्षेत्र का निवासी हो।

हंगामे की भेंट चढ़ी लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही

नई दिल्ली/एजेंसी

संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते दो बार स्थगित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से सदन को चलने देने का अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों के अनुरुप चर्चा को तैयार है। फिर भी विपक्ष दोहरे मानदंड अपना रहा है। संसदीय कार्यमंत्री रिजिजू ने लोकसभा में दो बार के स्थगन के बाद विपक्ष से अनुरोध किया कि वे सदन को चलने दें। उन्होंने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा हुई थी जिसे अंतिम रुप नहीं दिया गया है। विपक्ष सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहता है जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है लेकिन विपक्ष के सभी मुद्दों पर एक साथ चर्चा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में ऑपरेशन सिंदूर पर किस नियम के तहत कितनी देर चर्चा होनी है तय किया गया है। एक साथ सभी मुद्दों पर चर्चा संभव नहीं है। विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है और सरकार इसे स्वीकार कर रही है ऐसे में विपक्ष का दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। देश के करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने विपक्ष से सरकार के अनुरोध पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन में प्लेकार्ड और पोस्टर लाना गणतंत्र के लिए ठीक नहीं है। शोर-शराबा रुकते न देख उन्होंने कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति रही और उपसभापति हरिवंश को कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ी। लोकसभा में सुबह कार्यवाही की शुरूआत में अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को हंगामे के दौरान नारेबाजी नहीं करने और तख्तियां लेकर नहीं आने के लिए कहा। उनके बार-बार कहने पर भी हंगामा जारी रहा, जिसके चलते कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गयी। दोपहर 12 बजे भी कार्यवाही नहीं चली और दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

मोदी की यात्रा के दौरान ब्रिटेन एफटीए पर हस्ताक्षर होने की संभावना

मोदी 23 से 26 जुलाई तक रहेंगे ब्रिटेन, मालदीव की यात्रा पर

नई दिल्ली/एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल से शुरू हो रही ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

श्री मोदी कल ब्रिटेन की यात्रा पर लंदन के लिए रवाना होंगे और वहां से सीधे मालदीव जाएंगे और 26 जुलाई को माले में मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के बाद स्वदेश लौटेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री की दो देशों की यात्रा की जानकारी दी। श्री मिस्री ने संकेत दिये कि श्री मोदी की ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान भारत ब्रिटेन एफटीए की घोषणा हो सकती है। उन्होंने ये संकेत भी दिये कि श्री मोदी ब्रिटिश सरकार के साथ खालिस्तानी आतंकवादियों एवं ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर दो टूक शब्दों में भारत की चिंताओं को रखेंगे। मिस्री ने कहा, "...प्रधानमंत्री कल, 23 जुलाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीरस्टार्मर के साथ चर्चा के लिए ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वह किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे। भारत और ब्रिटेन, दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत की भी योजना है। पदभार ग्रहण करने के बाद से यह प्रधानमंत्री की ब्रिटेन की चौथी यात्रा होगी।" प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा पर विदेश सचिव ने कहा, "प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा 25 और 26 जुलाई को होगी। वह मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं।

बोइंग ने भारत को तीन अपाचे हेलिकॉप्टर सौंपे, सेना की बढ़ेगी ताकत

नई दिल्ली/एजेंसी

दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा करेगा। बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित अपाचे हेलीकॉप्टर भारत आ गए हैं। भारतीय सेना ने बताया कि अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की डिलीवरी हो गई है। भारतीय सेना इन हेलीकॉप्टरों को जोधपुर में तैनात करेगी। हालांकि, यह आपूर्ति करीब 15 महीने की देरी के बाद की गई है।

क्या है अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर

अपाचे दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यह एक नाइट विजन एयरक्राफ्ट है। अमेरिकी रक्षा दिग्गज कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित यह हेलीकॉप्टर आधुनिक संचार, नेविगेशन, सेंसर और हथियार प्रणाली से लैस है। यह एक नाइट विजन एयरक्राफ्ट है। साथ ही पायलटों को दिन और रात दोनों स्थितियों में लक्ष्यों की पहचान करने और उन पर हमला करने में मदद करता है। इसके जरिये बारिश, धूल या कोहरे के कारण खराब दृश्यता में भी हमला किया जा सकता है। बोइंग के मुताबिक अपाचे 21 हजार फीट की ऊंचाई तक 280 किमी प्रतिघंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें 16 एंटी टैंक एजीएम-114 हेलफायर मिसाइल छोड़ने की क्षमता है। इसमें 30 मिलीमीटर की दो गन हैं, जिनमें एक बार में 1,200 गोलियां भरी जाती हैं। अपाचे में 16 एंटी टैंक एजीएम-114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल लगी होती हैं। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्मर्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, बीएमपी वाहनों को पल भर में उड़ा सकती है। भारत ने 2015 के एक समझौते के तहत भारतीय वायु सेना के लिए 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे थे।

एअर इंडिया ने अपने बोइंग 787 और 737 विमानों की जांच के बाद कहा- कोई समस्या नहीं मिली

नई दिल्ली/एजेंसी

एअर इंडिया ने मंगलवार को कहा कि उसने अपने सभी बोइंग 787 और 737 विमानों के ईंधन नियंत्रण स्विच (एफसीएच) के लॉकिंग तंत्र का एहतियाती निरीक्षण पूरा कर लिया है। जांच में कोई समस्या नहीं पायी गयी है। इसके साथ ही समूह के दोनों एयरलाइनों ने 14 जुलाई 2025 को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के जारी निदेर्शों का पालन किया है। एअर इंडिया ने एक?स पोस?ट में कहा कि बोइंग 787 और 737 विमानों के ईंधन नियंत्रण स्विच के लॉकिंग तंत्र के निरीक्षणों में कोई समस्या नहीं पाई गई।

कंपनी ने कहा कि एअर इंडिया ने 12 जुलाई को स्वैच्छिक निरीक्षण का कार्य शुरू किया था, जिसे डीजीसीए की निर्धारित तय समय-सीमा के भीतर इसे पूरा कर लिया गया है।

कांवड़ मार्ग पर होटलों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा

नई दिल्ली/एजेंसी

भोजनालयों के लिए क्यूआर कोड मामले पर सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने क्यूआर कोड संबंधी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग के सभी होटल मालिकों को लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यू कोड अनिवार्य करने के मुद्दे पर कोई निर्देश नहीं दिया। अदालत ने कहा कि अभी क्यूआर कोड के मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है और मुख्य याचिका पर सुनवाई के दौरान इस पर विचार किया जा सकता है। मुख्य याचिका अभी अदालत में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार के उस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें सरकार ने कांवड़ मार्ग पर सभी खाने-पीने की दुकानों और भोजनालयों पर क्यूआर कोड स्टीकर प्रदर्शित करने और साथ ही दुकानों के बाहर बैनर लगाकर दुकान मालिक के नाम और पहचान को प्रदर्शित करने को कहा था।

इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा था। सरकार के आदेश के खिलाफ याचिकाएं शिक्षाविद अपूर्वानंद झा, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और अन्य ने दायर की थीं।

याचिकाकर्ताओं को डर- इससे सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने का खतरा

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहना भेदभाव है और साथ ही यह कांवड़ियों के लिए संकेत है कि उन्हें किस दुकान को नजरअंदाज करना है। उनके अनुसार, दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहना भेदभाव है और साथ ही यह कांवड़ियों के लिए संकेत है कि उन्हें किस दुकान को नजरअंदाज करना है। याचिकाकताओं ने कहा कि उन्हें डर है कि सरकार के इस फैसले से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा और इससे भीड़ हिंसा की आशंका भी बढ़ जाएगी, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के दुकानदारों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हो सकती हैं। याचिकाकताओं के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर और कांवड़ यात्रा पर सत्तापक्ष-विपक्ष में तीखी बहस

एजेंसी

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही 'ऑपरेशन सिंदूर' और विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। समाचार एजेंसी से बातचीत में विभिन्न नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर, कांवड़ यात्रा समेत अन्य मुद्दों पर बात की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सभी दलों को पहले ही विश्वास में लिया था। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह उन नेताओं से डरती है, जो भारत और राष्ट्रवाद के पक्ष में बोलते हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने विदेश जाकर ऑपरेशन सिंदूर और भारत की ताकत का समर्थन किया, जिससे कांग्रेस को डर है कि ये लोग उनके राजनीतिक दुश्मन बन जाएंगे।

उन्होंने कांवड़ यात्रा पर विपक्ष के सवालों को लेकर तंज कसा और कहा कि विपक्ष को उम्मीद थी कि यात्रा में पत्थरबाजी होगी, लेकिन इस बार यात्रियों ने एक-दूसरे का स्वागत किया और माला पहनाई, जिससे विपक्ष परेशान है। भाजपा सांसद रवि किशन ने ऑपरेशन सिंदूर को 'विजय का उत्सव' करार देते हुए कहा, 'हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। यह हमारे लिए गर्व का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को

इसके लिए धन्यवाद। वहीं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा, पहलगाम की घटना के बाद भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसे कई देशों ने समर्थन दिया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सत्र को 'ऑपरेशन सिंदूर' का उत्सव बताया और कहा, जो लोग सेना के शौर्य और देश की जीत पर सवाल उठाते हैं, वे देश की सेवा को कमतर आंक रहे हैं। भारत आज सीधा जवाब देता है, फिर भी विपक्ष सवाल उठाता है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से बचने का आरोप सत्तापक्ष पर लगाया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, हम चाहते हैं कि सदन में हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो। सरकार को ऑपरेशन सिंदूर और विजय उत्सव के बारे में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। हमने विशेष सत्र की मांग की थी, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की उपलब्धियों पर सवाल उठाते हुए कहा, पहलगाम के आतंकी कहां गए? सरकार को जवाब देना चाहिए। विदेश नीति बर्बाद है, किसान परेशान हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। इन मुद्दों पर भी चर्चा जरूरी है। कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम ने भी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना पर व्यापक बयान की मांग की और कहा, भारत गुट ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

पूरा भारत 'मेक इन इंडिया' का लाभ ले रहा, राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा ही नहीं: सुशीबेन शाह

एजेंसी

मुंबई। शिवसेना प्रवक्ता सुशीबेन शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मेक इन इंडिया को असेंबल इन इंडिया कहने पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। सुशीबेन शाह ने कहा कि मेक इन इंडिया का लाभ आज पूरा भारत उठा रहा है और पूरी दुनिया इसकी सराहना कर रही है। सोमवार को से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन क्षेत्र में भारत बहुत आगे है। यहां सबसे ज्यादा फोन बनाए जाते हैं, जो दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी भारत आज अव्वल नंबर पर है। मेक इन इंडिया हर लिहाज से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, हर सेक्टर में मोदी सरकार मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने में लगी है। राहुल गांधी को पता है कि वह कांग्रेसी फैक्ट्री में गए थे। तभी वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। फैक्ट्री में मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग का फायदा नहीं लिया गया, इसीलिए वह असेंबल हो रहा होगा। लेकिन, आज पूरे भारत में मेक इन इंडिया का लाभ उठाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, खासकर राहुल गांधी, क्योंकि उन्हें ऐसा राजनेता पसंद नहीं जो उनसे बेहतर और समझदारी से बोलता हो। उन्होंने कहा, एक बात स्पष्ट कर दूं कि शशि थरूर एक सच्चे राष्ट्रवादी और देशभक्त हैं। उन्होंने हमेशा राष्ट्रहित में बात की है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति को विदेशों में रखा। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ खड़े हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस शशि थरूर से क्यों डरती है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देना चाहिए।

मैं विपक्ष का नेता हूं, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा: राहुल गांधी

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। पहले ही दिन हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को बार-बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा सदन में चर्चा कराने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। जिसके चलते लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं विपक्ष का नेता हूं, लेकिन मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सवाल ये है कि जो सदन में रक्षा मंत्री को बोलने देते हैं, उनके (सरकार) लोगों को बोलने देते हैं, लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता कुछ कहना चाहता है तो अनुमति नहीं है। मैं विपक्ष का नेता हूं, मेरा हक है, तो मुझे कभी बोलने ही नहीं देते हैं। ये एक नया एप्रोच है। उन्होंने आगे कहा कि परंपरा कहती है कि यदि सरकार की तरफ से लोग बोल सकते हैं, तो हमें भी बोलने की जगह मिलनी चाहिए। हम दो शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को इसकी इजाजत नहीं है। वहीं, पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का टाइम तय किया हुआ है। ढाई बजे सारे मेंबर्स की बैठक होगी, जिसमें किस-किस मुद्दे पर चर्चा करनी है, ये तय होगा। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेकर आ रही है और विपक्ष सदन के वेल पर आकर हंगामा कर रहा है। हमने शुरू से अपील की है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मानसून सत्र के पहले दिन इस तरह विरोध करना सही नहीं है।

अराजकता फैलाना कांग्रेस की आदत बन गई है: जगदंबिका पाल

नई दिल्ली। मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में विपक्ष की ओर से हंगामा किए जाने पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वह बस सदन की कार्रवाई को बाधित करना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्र के दौरान अराजकता फैलाना कांग्रेस की आदत बन गई है। से बातचीत के दौरान जगदंबिका पाल ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन, कांग्रेस की आदत है कि वह सदन के अंदर चर्चा नहीं, हंगामा ही चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जवाब दे रहे हैं और आज एक बार फिर संसद के सुचारू संचालन की अपील कर रहे हैं। अगर कोई सवाल गृह मंत्रालय से जुड़ा है तो गृह मंत्री जवाब देंगे, अगर संसदीय मामलों से जुड़ा है तो संबंधित मंत्री जवाब देंगे, और जब प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण जैसे मुद्दे पर बोलने की जरूरत होती है तो वह बोलते हैं। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि सत्र के दौरान अराजकता फैलाना कांग्रेस की आदत बन गई है। राहुल गांधी खुद सत्र में नहीं बैठते। सदन में चर्चा के दौरान वह बोलते नहीं हैं। वह सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। बिहार एसआईआर पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने घर-घर जाकर डोर-टू-डोर वोटर का वेरिफिकेशन किया है। यह प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं हो रही है, जिसे लेकर विपक्ष हंगामा मचा रहा है। चुनाव से पहले यह प्रक्रिया अपनाई जाती है।

पीएम मोदी ने 'ट्रेकोमा फ्री इंडिया' का किया जिक्र, बोले- 'आरोग्य के क्षेत्र में भारत कर रहा बेहतरीन काम'

एजेंसी

नई दिल्ली। एक वक्त था जब ट्रेकोमा जैसी आंख की बीमारी भारत में अंधेपन की बड़ी वजह मानी जाती थी। गंदगी और इलाज की कमी से ये बीमारी लाखों लोगों को प्रभावित कर रही थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत ने वर्षों की मेहनत, जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए इस बीमारी को पीछे छोड़ दिया। इसकी पुष्टि खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने की थी। इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार गर्व से देश के सामने रखा है। मानसून सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए एक बार फिर उन्होंने ट्रेकोमा से भारत की जीत को बड़ी सफलता बताया है। पीएम मोदी ने मानसून सत्र की शुरुआत से पहले कहा, 'डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि भारत ने आंख की बीमारी ट्रेकोमा से खुद को मुक्त कर लिया है। आरोग्य के क्षेत्र में

हमने अच्छा काम किया है। इससे पहले भी पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में इस पर बात कर चुके हैं। 29 जून को प्रसारित हुए अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात में उन्होंने देश के स्वास्थ्यकर्मियों, डॉक्टरों और जागरूक नागरिकों को इस सफलता का श्रेय देते हुए कहा कि यह भारत की जन-भागीदारी और स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा था, ट्रेकोमा एक गंभीर संक्रामक नेत्र रोग है, जो आमतौर पर गंदगी, साफ-सफाई की कमी और बैक्टीरिया के संक्रमण से फैलता है। यह आंखों में सूजन पैदा करता है और समय पर इलाज न होने पर अंधेपन का कारण भी बन सकता है। एक समय था जब भारत में यह बीमारी व्यापक रूप से फैली हुई थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर इसके उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाए। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों ने साफ-सफाई और स्वच्छ पेयजल की पहुंच को बढ़ाकर बीमारी को जड़ से खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई। बता दें कि ट्रेकोमा एक खास बैक्टीरिया (क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस) के कारण होता है। यह बीमारी गंदगी, साफ-सफाई की कमी और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। किसी बीमार व्यक्ति की आंख, नाक या गंदे हाथों को छूने से, या उसके इस्तेमाल किए हुए रुमाल और तौलिए से भी ये बीमारी दूसरे लोगों में पहुंच सकती है।

वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन: एक श्रद्धालु की मौत, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जताया दुख

एजेंसी

कटरा। जम्मू-कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। बाणगंगा के पास तेज बारिश के चलते अचानक भूस्खलन हो गया, जिससे कई श्रद्धालु मलबे में फंस गए। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं।पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार, बाणगंगा क्षेत्र में अचानक पहाड़ से बड़े-बड़े पत्थर और मलबा आने से यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान कई श्रद्धालु फंस गए। भूस्खलन के बाद मौके पर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और श्राइन बोर्ड की टीमें मलबा हटाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी हुई हैं। मौसम विभाग की ओर से पहले ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। इस दुखद घटना पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उपराज्यपाल कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनोज सिन्हा के हवाले से एक पोस्ट में लिखा, ÷मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण भूस्खलन हादसे से अत्यंत दुखी हूं, जिसमें एक श्रद्धालु की जान चली गई। घायल यात्रियों को सर्वोत्तम चिकित्सकीय सुविधा और हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मैं स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हूं। हादसे के बाद आवागमन को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। हालांकि, इस संबंध में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: सबूतों के अभाव में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों को किया बरी

एजेंसी

मुंबई। वर्ष 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया है। इस मामले में 12 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट की ओर से इन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने विशेष टाडा न्यायालय की ओर से दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें से 5 को मृत्युदंड और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

यह फैसला 19 साल बाद आया है। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एस. चांडक की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों में कोई ठोस आधार नहीं था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।हाईकोर्ट ने न केवल आरोपियों की अपील को स्वीकार किया, बल्कि राज्य सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें मृत्युदंड की मांग की गई थी।

यह मामला 11 जुलाई 2006

का है, जब मुंबई की लोकल ट्रेनों में शाम के समय मात्र 11 मिनट के अंदर सात अलग-अलग जगहों पर सीरियल बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 189 लोगों की जान चली गई थी और 827 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। नवंबर 2006 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके बाद 2015 में ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें 5 को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जनवरी 2025 में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई थी, और तब से कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। येरवडा, नाशिक, अमरावती और नागपुर जेल में बंद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

'विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा को तैयार हूं', सदन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा के मानसून सत्र में सोमवार को बार-बार व्यवधान देखने को मिला। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक। हंगामे के बावजूद, केंद्र सरकार ने कहा कि वह विपक्ष की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार पहलगाम हमले सहित राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर विस्तृत बहस के लिए पूरी तरह तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं सांसदों को भरोसा दिलाता हूं कि सुरक्षा से जुड़े किसी भी मुद्दे पर, चाहे चर्चा कितनी भी लंबी क्यों न हो, हम पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार हैं। जब भी स्पीकर समय देंगे, हम चर्चा में भाग लेंगे। यह बात उन्होंने उस समय कही जब विपक्षी सांसदों ने पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में गैरहाजिरी पर सवाल उठाए।संसदीय

कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दोपहर 2:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक होगी, जिसमें चर्चा के लिए मुद्दों की लिस्ट तय की जाएगी। रिजिजू ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ था कि इस सत्र में ज्यादा से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के सांसद सदन के वेल में आकर विरोध कर रहे हैं। सत्र के पहले ही दिन इस तरह का विरोध करना ठीक नहीं है। अगर किसी को कोई मुद्दा उठाना है तो उसे नियमों के तहत चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले, स्पीकर ओम बिरला ने शुरुआती व्यवधान के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी।

कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा, तो ओम बिरला की गैरमौजूदगी में पीठासीन जगदंबिका पाल को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए फिर से स्थगित करनी पड़ी।

हर नागरिक की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता : सीएम योगी आदित्यनाथ

एजेंसी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन किया। इस दौरान यहां प्रदेश भर से लगभग 50 से अधिक पीड़ित पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी हर पीड़ित के पास स्वयं पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। हर समस्या का निराकरण होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए दिव्यांगजनों की बात पर गौर करते हुए उन्हें मोटराइज्ड ट्राई साइकिल दिलाने को कहा। इसके अलावा, पुलिस, राजस्व, चिकित्सा सहायता, रोजगार, शिक्षा, आवास, कब्जा, परिवार आदि से जुड़े मामले भी आए, जिस पर प्रार्थना पत्र लेकर

मुख्यमंत्री योगी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जनता की समस्या सुनते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को त्वरित और संतुष्टि परक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सबको न्याय मिलेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अभिभावकों के साथ आए बच्चों से भी बातचीत की। उनका हालचाल जाना, दुलार किया। बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली। सीएम योगी ने चॉकलेट-टॉफी प्रदान कर बच्चों को उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस (सीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनता दर्शन की फोटो शेयर की और लिखा, प्रदेश के हर नागरिक की सेवा एवं सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता...यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर जनता दर्शन में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने जन-समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

संसद सुचारू रूप से चलाना सबकी जिम्मेदारी - रिजिजू

एजेंसी

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि संसद को सुचारू रूप से चलाना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है और वैविचारिक विविधता के बावजूद सभी दलों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को यहां संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, सर्वदलीय बैठक में आज विभिन्न दलों के 54 सदस्यों ने भाग लिया। यह बैठक बहुत सकारात्मक रही और सदस्यों ने सकारात्मक रूप से ही अपने विचार प्रस्तुत किए। सभी दलों के नेताओं ने सुझाव दिए और सरकार ने उन सभी की सुझाव को नोट कर लिया है। सभी दलों के नेताओं से अनुरोध किया गया है कि मानसून सत्र उत्पादकता पूर्ण रहे ,यह सभी को सुनिश्चित करना चाहिए। संसद सत्र का शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संचालन महत्वपूर्ण है। हम अलग-अलग दलों और अलग-अलग विचारधाराओं से हो सकते हैं लेकिन संसद को सफलतापूर्वक चलाना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी दलों की बात ध्यान से सुनी और उस पर ध्यान दिया है। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को अच्छे समन्वय के साथ काम करना चाहिए।

तेजस्वी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर बहस की मांग की, सरकार को दी चेतावनी

एजेंसी

पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के विरोध में विपक्ष मोर्चा खोल चुका है। बिहार विधानमंडल के सोमवार से शुरू मानसून सत्र के पहले दिन मतदाता परीक्षण को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन से साफ है कि यह सत्र हंगामेदार होगा और एसआईआर मुख्य मुद्दा होगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मतदाता पुनरीक्षण पर बहस कराने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अभी महागठबंधन के विधायक दलों की अहम बैठक हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि हम सभी की विधानसभा अध्यक्ष से मांग है कि मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विधानसभा में चर्चा कराई जाए।

लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। अगर यहीं से लोकतंत्र समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में जानबूझकर गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं ताकि चुनाव में उन्हें वोट देने से रोका जा सके। अगर चर्चा नहीं हुई, तो कल बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया जाएगा।उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है, तो आने वाला समय इन लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के सभी नेताओं को पत्र लिखा है। पार्लियामेंट में भी लोग इसे मजबूती के साथ उठा रहे हैं। बिहार में भी मजबूती के साथ हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। सरकार को किसी भी कीमत पर इस मुद्दे पर चर्चा करानी ही पड़ेगी। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग हर एक मुद्दे को सदन में उठाएंगे।

सोशल मीडिया पर तमंचा लहराते हुए वीडियो पोस्ट करने वाला हथियार समेत गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिमी जिले की सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवक को तमंचा लहराते हुए वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दक्षिण पश्चिमी जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अमित गोयल ने बताया कि आरोपित ने तमंचा लहराते हुए वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। पुलिस को इसकी जानकारी मिलने के बाद तत्काल जांच शुरू की और आरोपित को तमंचे, कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को बताया है कि वह इलाके के लोगों में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ऐसी वीडियो पोस्ट करता था। आरोपित की पहचान 19 वर्षीय नौशाद के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, 18 जुलाई को सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वीडियो पोस्ट करने वाला नौशाद पुलिस की टीम को सफदरजंग हास्पिटल फैक्टरी रोड के पास बाइक से घूमता दिखाई दिया। पुलिस ने तत्काल योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर अस्पताल के गेट संख्या सात के पास से उसे एक बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया। जांच में बाइक भी हौज खास इलाके से चोरी की निकली।

साइबर सेल ने ठगी के मामले में तीन आरोपितों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली द्वारका की साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के टोंक, सीकर, जयपुर और हरियाणा के सिरसा से तीन शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। द्वारका की साइबर सेल की गिरफ्त में आए ये ठग आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर आम लोगों को कभी ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर, तो कभी डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगी का शिकार बना रहे थे। पकड़े गए आरोपितों की पहचान राजस्थान निवासी दीपक वर्मा , सुरेन्द्र कुमार डूडी और राजवीर के रूप में हुई है। द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अंकित सिंह ने बताया कि द्वारका जिले की साइबर थाने में पिछले कुछ महीनों में साइबर ठगी की कई शिकायतें सामने आई थीं। जांच में मिले डिजिटल फुटप्रिंट्स और लेन-देन के रिकॉर्ड से पुलिस को इस बात के पक्के सुराग मिले कि इन घटनाओं की जड़ें राजस्थान और हरियाणा के दूरदराज के इलाकों में हैं। इसके बाद एक टीम गठन किया गया। टीम ने इन राज्यों में जाकर गुप्त तरीके से निगरानी की और सबूत जुटाने के बाद एक सप्ताह के भीतर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया।

चोरी के मोबाइल नेपाल में सप्लाई करने वाला आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चोरी के मोबाइल सप्लाई करने वाले कुख्यात अपराधी सतेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सुर्जी को करोल बाग स्थित उसकी दुकान से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से 42 महंगे मोबाइल फोन, जिनमें 16 आई फोन सहित अन्य एंड्रॉयड फोन शामिल हैं। जांच में पता चला है कि आरोपित चोरी और स्नैचिंग के मोबाइल दिल्ली से खरीदकर उन्हें नेपाल की ग्रे मार्केट में बेचता था। अब तक वह 300 से 400 मोबाइल फोन नेपाल सप्लाई कर चुका है।क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदौरा के अनुसार 19 जुलाई को एसआई अमित कुमार को सूचना मिली थी कि करोल बाग के बीडनपुरा गांव में स्थित एक दुकान में चोरी के मोबाइल की डीलिंग हो रही है। सूचना को पुख्ता कर पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी कर आरोपित को दबोचा। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह पहले भी 10 आपराधिक मामलों जैसे मोबाइल चोरी, घर में चोरी, झपटमारी और डकैती में गिरफ्तार हो चुका है। तिहाड़ जेल में रहते हुए उसने अन्य अपराधियों से संपर्क साधा और बाहर आकर फिर से इस अवैध कारोबार में लिप्त हो गया। जांच में पता चला है कि पकड़ा गया आरोपित सतेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सुर्जी मूलत- गांव गिलोली, जिला लखीमपुर खीरी उप्र का रहने वाला है।

संविधान की प्रति जेब में रखना और संवैधानिक पद पर हमला विरोधाभाषी - गजेंद्र सिंह शेखावत

नई दिल्ली । लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज कसा है। शेखावत ने कहा कि संविधान की एक प्रति जेब में रखना और संवैधानिक पद पर हमला विरोधाभाषी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि संविधान की एक प्रति जेब में रखना और साथ ही संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना और उनकी पवित्रता को कम करना बेहद विरोधाभाषी है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। यह पहली बार नहीं है, बल्कि देश में चौथी बार ऐसा हो रहा है, ऐसे में इस तरह की अनुचित टिप्पणी करना उनकी अपनी विश्वसनीयता को ही कम करता है। संसद के आगामी मानसून सत्र पर शेखावत ने कहा कि मेरा मानना है कि देश के सामने कई महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मुद्दे हैं, जिन पर खुली चर्चा और संवाद होना चाहिए। संसद संवाद का प्लेटफार्म है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल रचनात्मक विचार-विमर्श के लिए किया जाएगा, न कि इसे व्यवधान या अराजकता का मंच बनाया जाएगा।

दिल्ली में विभिन्न राज्यों की कला एवं संस्कृति का होगा प्रचार-प्रसार : मुख्यमंत्री

एजेंसी

नई दिल्ली । दिल्ली में देश के विभिन्न राज्यों की कला, संस्कृति को प्रभावी रूप से विस्तार दिया जाएगा। इसमें दिल्ली सरकार का कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग अपने कार्यक्रमों और आयोजनों का विस्तार कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली सरकार की ओर से इसकी जानकारी दी गयी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राज्य का कला, संस्कृति और भाषा विभाग अपनी गतिविधियों को विशेष स्थलों से निकालकर आम लोगों तक ले जाएगा, ताकि उनमें जन-भागीदारी बढ़े। इसके लिए दिल्ली में मनाए जाने वाले क्षेत्रीय पर्व-त्योहारों में इनसे जुड़े कलाकारों को बुलाया जाएगा, जिससे कि लोगों की ऐसे आयोजनों में दिलचस्पी बढ़े। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बच्चों को गैर हिंदी भाषा पढ़ाने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं, ताकि वे दूसरे प्रदेशों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को भी समझ सकें। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के

साथ एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली सचिवालय में हाल ही में आयोजित इस बैठक में विभाग के मंत्री कपिल मिश्रा सहित विभिन्न निकायों के सचिव, उप सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य दिल्ली को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाना और समाज के सभी वर्गों को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना था। मुख्यमंत्री ने माना कि यह विभाग वर्षों से देश और दिल्ली की कला संस्कृति का प्रचार-प्रसार कर रहा है। लेकिन अब इसके उद्देश्य को और विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग के आयोजनों में महिला कला प्रदर्शनी, दिल्ली नृत्य एवं संगीत महोत्सव, भक्ति संगीत उत्सव, हास्य रंग उत्सव, पेंटिंग्स प्रतियोगिता, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, राम नवमी आदि पर कार्यक्रम शामिल हैं। ऐसे कार्यक्रमों व आयोजनों को स्थान विशेष से निकालकर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आयोजित किया जाएगा, ताकि इनसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी दिल्ली में विभिन्न राज्यों के लोग वर्षों से निवास कर रहे हैं, इसलिए उनकी संस्कृति और सामाजिक सारोकार भी विस्तार पा रहे हैं। इसका एक लाभ यह हुआ है कि दिल्ली में अब छठ पूजा, दुर्गा पूजा, गणेशोत्सव, लोहड़ी व अन्य प्रादेशिक पर्व भी श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वे इन पर्व-उत्सवों के लिए आंचलिक कलाकारों को दिल्ली बुलाएं और उनके नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करें। अधिकारियों से इसके लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान भी है। लिहाज, वो चाहती हैं कि विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति हर गली तक पहुंचे और हर व्यक्ति इससे जुड़ाव महसूस करे। दिल्ली के बच्चे दूसरे राज्यों की भाषा भी सीखें, ताकि वे संबंधित राज्यों की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी समझ सकें।

समाज कल्याण मंत्री इंद्राज ने फूल बरसाकर किया कांवड़ियों का अभिनंदन

एजेंसी

नई दिल्ली। समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने रोहिणी सेक्टर-20 में शिव मंदिर पर कांवड़ियों का फूल बरसाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने कांवड़ियों की कठिन यात्रा के प्रति आभार एवं शुभकामनाएं व्यक्त कीं। मंत्री रविंद्र इंद्राज ने कहा कि दिल्ली सरकार श्रद्धालुओं की आस्था और जनभावनाओं का पूर्ण सम्मान करती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा के दौरान अभूतपूर्व और ऐतिहासिक व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली शिवमय हो गई है। विभिन्न स्थानों पर ज्योतिर्लिंगों की प्रेरणा से 17 भव्य स्वागत द्वार बनाए गए हैं। दिल्ली में कुल 374 कांवड़ शिविर स्थापित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी से अधिक संख्या में हैं। इन शिविरों में ठहरने, पेयजल, भोजन एवं बिजली की समुचित व्यवस्था की गई है। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि दिल्ली से होकर गुजरने वाले और दिल्ली से जाने वाले कांवड़ियों की संख्या करोड़ों में है। कांवड़ यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव है और दिल्लीवासी श्रद्धालुओं की सेवा और सहयोग से इस आयोजन को सफल बना रहे हैं।

कांग्रेस नेताओं ने दी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि

एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की पुण्यतिथि पर दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पुष्पांजलि सभा में सम्मिलित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल में शामिल अन्य मंत्रियों ने भी सोशल माडिया एक्स के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पुष्पांजलि सभा में पूर्व सांसद और शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित, पुत्री लतिका, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक हसन अहमद, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ, कम्यूनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज समेत पार्टी कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने शीला दीक्षित के चित्र पर माल्यार्पण किया साथ ही श्रद्धा के फूल अर्पित किए। सभा के बाद पत्रकारों को संबंधित करते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि शीला दीक्षित के विकास को

आज भी लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली को संवारा और आज भी दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश में यह माना जाता है कि अगर किसी ने अच्छे विकास का मॉडल दिया है, तो वह केवल शीला दीक्षित ने दिया है। उन्होंने कहा , हम यहां शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देने आए हैं। आज उन्हें हम सबको छोड़कर गए छह साल हो गए। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि वे भी आधुनिक दिल्ली की नींव रखने वाली शीला दीक्षित के दिखाए हुए रास्ते पर आज भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनकी सोच की जरूरत है, हम लगातार उनके दिखाए हुए रास्ते को प्रशस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास में उनके अतुलनीय योगदान और दिल्लीवासियों के प्रति उनके स्नेह, सेवा और समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के नए विदेश मंत्री चो ह्यून को दी बधाई, बोले- साथ मिलकर काम करने को तत्पर

एजेंसी

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को चो ह्यून को कोरिया गणराज्य का नया विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। एक्स पर एक पोस्ट में, जयशंकर ने लिखाः कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त होने पर राजदूत चो ह्यून को बधाई। हमारी विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं। राजदूत चो ह्यून, एक अनुभवी राजनयिक, पहले संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण कोरिया के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थे और दुनिया भर में महत्वपूर्ण राजनयिक भूमिकाएं निभा चुके हैं। विदेश मंत्री चो ह्यून ने सबको हैरान करते हुए सोमवार को अपने पुराने राजनयिक आचरण के लिए सार्वजनिक माफीनामा जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली यून सुक येओल सरकार के दौरान राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनके मंत्रालय का दुरुपयोग किया गया था। चो ने यह टिप्पणी राष्ट्रपति ली

जे म्युंग के पहले विदेश मंत्री के रूप में अपने शपथ ग्रहण समारोह में की, जिन्होंने दिसंबर में मार्शल लॉ लागू करने के बाद यून को पद से हटाए जाने के बाद पिछले महीने पदभार ग्रहण किया था। चो ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में, राजनयिक मुद्दों का इस्तेमाल घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया है, और कूटनीति के क्षेत्र में, जहाँ राष्ट्रीय हित और व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अक्सर स्पष्ट रूप से देखा गया है। उन्होंने कहा, विदेश मंत्री होने के नाते, मैं जनता से तहे दिल से माफी मांगता हूं। उन्होंने आगे कहा कि विदेश मंत्रालय पूरी प्रक्रिया के दौरान जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। उन्होंने इस तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संगठन में सुधार का संकल्प लिया। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, चो ने कहा कि बढ़ती भू-राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर में, कोरियाई प्रायद्वीप में शांति स्थापित करना दक्षिण कोरिया की सर्वोच्च कूटनीतिक प्राथमिकता होनी चाहिए।उन्होंने कहा, हमें प्रायद्वीप में तनाव कम करने और उत्तर कोरिया के साथ बातचीत का रास्ता बनाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहिए।+

फर्जी लॉटरी और गिफ्ट स्कीम से ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज-1 ने राजधानी और एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के जुड़े दो विदेशी समेत छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अंतरराष्ट्रीय ठगी गिरोह के सदस्य फर्जी लॉटरी, उपहार और पुरस्कार योजनाओं के माध्यम से आम लोगों के धोखाधड़ी करते थे।गिरोह में विदेशी नागरिकों के साथ भारतीय सहयोगी भी शामिल हैं, जो फर्जी बैंक खातों और डिजिटल लेन-देन के जरिये धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस की पकड़ में आए आरोपितों की पहचान नाइजीरिया के रहने वाले शेड्रैक ओनाइनोर उर्फ हैप्पी (29) और संडे जॉन उर्फ लिबर्टी (40) के अलावा बरेली, उत्तर प्रदेश के निवासी विकास (25), शाहरुख खान (23), राकेश उर्फ ललू (22) और दिल्ली के नांगलोई निवासी शाहिद रज़ा (45) के रूप

में हुई है।पुलिस इन आरोपितों से पूछताछ कर गिरोह के जुड़े अन्य सदस्यों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 3.63 लाख नकद, विभिन्न मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक और यूपीआई आधारित धोखाधड़ी से जुड़े मोबाइल डेटा बरामद किए हैं। पुलिस को 18 से अधिक फर्जी बैंक खातों की जानकारी भी मिली है। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) विक्रम सिंह के अनुसार सात जुलाई को गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने पंजाबी बाग स्थित सेंट्रल मार्केट चौक पर छापा मारा और शाहिद रज़ा को गिरफ्तार किया। उसके पास से 3.63 लाख नकद, नौ एटीएम कार्ड और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। जिसमें ठगी से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा पाया गया।

शाहिद की निशानदेही पर टीम ने खानपुर स्थित कृष्णा पार्क में छापेमारी कर नाइजीरियाई नागरिक शेड्रैक ओनाइनोर को गिरफ्तार किया, जो उस समय धोखाधड़ी की रकम एकत्र करने आया था। जांच में पाया गया कि शेड्रैक का वीज़ा 2018 में ही समाप्त हो चुका था और वह अवैध रूप से भारत में रह रहा था। उसके बाद अन्य आरोपितों को पकड़ा गया।

गिरोह का काम करने का तरीका

पुलिस के अनुसार नाइजीरियाई सदस्य शेड्रैक और संडे जॉन सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए लोगों को लॉटरी व गिफ्ट जीतने का झांसा देता था। जबकि उनके भारतीय सहयोगी शाहिद रज़ा और उसका दामाद शाहरुख खान बैंक खातों से पैसे निकालते और शेड्रैक को सौंपते थे। इसी क्रम में राकेश उर्फ ललू और विकास फर्जी आधार और पते के सहारे करीब 18-20 फर्जी बैंक खाते खोलते थे। उसके बाद खाते से जुड़ी एटीएम और सिम कार्ड शाहरुख को दी जाती थीं, जो फोनपे ऐप में यूपीआई आईडी बनाकर ट्रांजैक्शन करता था।

विधानसभा अध्यक्ष करेंगे नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता विधानसभा परिसर में विधायकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 21 से 23 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विधायकों को नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के उपकरणों और कार्यप्रणाली से परिचित कराना है, ताकि वे आगामी मानसून सत्र में प्रभावी रूप से भाग ले सकें। इस प्रशिक्षण का संचालन संसदीय कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा किया जाएगा। इस दौरान प्रतिभागी विधायकों को व्यावहारिक और समग्र प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।विज्ञप्ति के मुताबिक, यह दूरदर्शी पहल डिजिटल इंडिया के विजन को अपनाने की विधानसभा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नेवा का उद्देश्य विधानसभाओं के कार्य में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता लाना है, जिससे कि कागज रहित कार्यप्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके। नेवा प्रशिक्षण केंद्र में 18 कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं, जहां विधायकों का पहला बैच सोमवार 21 जुलाई 2025 को प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। प्रशिक्षण केंद्र और कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली विधानसभा की उस सक्रिय पहल को उजागर करती है, जिसके अंतर्गत विधायी प्रक्रियाओं को आधुनिक, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को 'सुप्रीम' राहत, ईडी की याचिका खारिज

एजेंसी

नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती के खिलाफ ईडी का समन रद्द कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी। यह मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) के प्लॉट आवंटन से जुड़ा हुआ है। ईडी ने इस सिलसिले में पार्वती को पूछताछ के लिए समन भेजा था। हालांकि, पार्वती ने कर्नाटक हाईकोर्ट में इस समन को चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने के बाद समन को रद्द कर दिया। पार्वती की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि उन्होंने मुडा से मिले सभी 14 प्लॉट स्वेच्छा से सरेंडर कर दिए हैं। इसके अलावा

उनके पास न तो किसी प्रकार की अपराध से अर्जित संपत्ति है और न ही उन्होंने ऐसी किसी आय का उपभोग किया है।

हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन, अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद पार्वती को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि मुडा घोटाला मामला करीब पांच हजार करोड़ रुपए का है। इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। बताया जा रहा है कि सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन ने कुछ जमीन गिफ्ट के तौर पर दी थी। यह जमीन मैसूरु जिले के कैसारे गांव में स्थित है। बाद में इस जमीन को मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) ने अधिग्रहित कर लिया। इसके बदले पार्वती को विजयनगर इलाके में 38,223 वर्ग फीट के प्लॉट दे दिए गए।आरोप है कि दक्षिण मैसूरु के प्रमुख इलाके में मौजूद विजयनगर के प्लॉट की कीमत कैसारे गांव की उनकी मूल जमीन से बहुत अधिक है। इसी को लेकर सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं।

रिश्तेदार के घर फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर डाली रेड, पुलिस ने तीन आरोपितों को किया गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली एक युवती ने अपने ही रिश्तेदार के घर फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर रेड डाली। अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवती तीन लाख कैश और लाखों के जेवरात लूट लिए।वारदात के बाद सभी धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले के तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

वजीराबाद पुलिस ने इस फर्जी छापेमारी की गुत्थी को सुलझाते हुए युवती समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपितों की पहचान शाइना उर्फ तन्नू (22), केशव प्रसाद (28) और विवेक सिंह (20) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपितों के पास से लूटे गए 1.75 लाख रुपये और लाखों रुपये के जेवरात व अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद आरोपित मौज मस्ती करने के लिए पहाड़ों पर निकल गए थे। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से इनकी लोकेशन का पता किया। बाद में तीनों आरोपितों को उत्तराखंड के मसूरी से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में शाइना ने बताया है कि उसे पता था कि उसके रिश्तेदार के घर मोटी रकम मौजूद रहती है। कारोबारी के यहां फर्जी छापेमारी की प्लानिंग कर वारदात को अंजाम दिया गया। उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजा बांठिया ने बताया कि 10 जुलाई को वजीराबाद निवासी इशरत जमील नामक व्यक्ति ने अपने घर पर सीबीआई रेड की सूचना दी थी। पीड़ित ने बताया कि वह अपने घर पर मौजूद थे। इस बीच मास्क लगाए तीन लोग घर में जबरन दाखिल हो गए। उनमें एक युवती भी थी। तीनों ने सफेद रंग की शर्ट और काले रंग की पेंट पहनी थी। तीनों ने आते ही एफआईआर दर्ज होने और घर की तलाशी लेने की बात की। इशरत जमील ने जब उनसे वारंट मांगा तो वह उसके साथ गाली-गलौज करने लगे।

धोखाधड़ी मामले में श्रेयस तलपड़े को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक

एजेंसी

नई दिल्ली। हरियाणा के सोनीपत जिले की एक मल्टी मार्केटिंग फर्म से जुड़े धोखाधड़ी और विश्वासघात मामले में अभिनेता श्रेयस तलपड़े को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई करते हुए अभिनेता को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी और हरियाणा पुलिस समेत अन्य को नोटिस जारी कर मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तलपड़े सहित अन्य अभिनेताओं और फर्म के ब्रांड एंबेसडर को एफआईआर में शामिल करने पर हरियाणा पुलिस से जवाब मांगा है। दरअसल, मामला इंदौर में रजिस्टर्ड एक कंपनी, ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के प्रमोशन से जुड़ा है, जो 50 लाख से ज्यादा लोगों के करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गई है। सोसाइटी ने श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को अपना ब्रांड एंबेसडर बताकर चिटफंड स्कीम निकाली थी। इस कंपनी पर आरोप है कि 6 साल में दोगुना रकम देने का झांसा देकर इसने 45 लोगों से 9.12 करोड़ रुपये ऐंठे। संचालकों ने एजेंट के तौर पर जुड़ने वालों को मैनेजर का पद देकर अन्य लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित

किया। करोड़ों रुपये हड़पने के बाद नवंबर में सोसाइटी के ऑफिस अचानक से बंद होने लगे, जिसके बाद पीड़ितों ने अलग-अलग जगह इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई। इस कड़ी में सोनीपत जिले के गांव हसनपुर के युवक विपुल ने भी श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ सहित 13 लोगों के खिलाफ मुरथल पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले में एफआईआर दर्ज कराई।

मामले में नामजद 13 लोगों में इंदौर के नरेंद्र नेगी, दुबई में रहने वाले समीर अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, परिक्षित पारसे, मुंबई निवासी आरके शेट्टी, मुख्य ट्रेनर राजेश टैगोर, संजय मुदगिल, हरियाणा हेड पप्पू शर्मा, चंडीगढ़ निवासी आकाश श्रीवास्तव, चेस्ट ब्रांच अधिकारी रामकंवार झा, पानीपत निवासी शबाबे हुसैन तो वहीं ब्रांड एंबेसडर के तौर पर अभिनेता आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े शामिल हैं।

अमित शाह ने हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का दिया निर्देश

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति व तीव्रता को देख एक बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह महसूस किया गया कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और मूसलाधार वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है, जिससे राज्य में व्यापक जनहानि, बुनियादी ढांचे और आजीविका को नुकसान और पर्यावरण क्षरण हुआ है। अमित शाह ने तुरंत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) रुड़की, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) पुणे, भूविज्ञानी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर के विशेषज्ञों की एक बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय टीम गठित करने का आदेश दिया। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने उनके ज्ञापन का इंतजार किए बिना ही, नुकसान का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) को पहले ही भेज दिया है। यह अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल 18 से 21 जुलाई तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार आपदाओं के समय बिना किसी भेदभाव के राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। इसी दिशा में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2023 के लिए बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश को 2,006.40 करोड़ रुपए के परिव्यय को पहले ही मंजूरी दे दी है और 7 जुलाई 2025 को 451.44 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी है। इसके अलावा, राज्य के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए, केंद्र सरकार ने तत्काल राहत उपायों के लिए 18 जून 2025 को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से हिमाचल प्रदेश को 198.80 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी है।

संपादक की कलम से

मानसून सत्र या तूफान सत्र

कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। देश का सियासी मौसम बता रहा है कि यह मानसून सत्र विपक्ष के तूफान सत्र में बदल सकता है। बड़ी बात यह है कि अब श्री मोदी के पास ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं बचा है, जिसे सहारा बनाकर वो मजबूती से खड़े रहें। सत्ता की शुरूआत में तो राम मंदिर बनाने से लेकर जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने जैसे कई वादे थे, जिनसे जनता की आंखों में न्यू इंडिया बनाने की चमक आ जाती थी। जनता वाकई यह मान बैठी थी कि हिंदुत्व को बचाने या राष्ट्रवाद को थोड़ा और उग्र कर देने से ही उसकी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। लेकिन हकीकत जनता भी देख रही है कि उसे अब भी शब्दों की जुगाली मिल रही है। मोदी को वाराणसी से जीतना था तो काशी को क्योटो बनाने की बात कहते थे, साथ में बुलेट ट्रेन की रफ्तार का पैकेज दे दिया। और 11 साल बाद मोतिहारी और मुंबई, गयाजी और गुरुग्राम, पटना और पुणे के गीत जनता को सुनाए जा रहे हैं। बिहार में अपने ताजा दौरे में मोदी ने यही किया। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा कहते हुए श्री मोदी एक बार भी जनता को ये आश्वासन नहीं दे सके कि उससे वोट देने का हक नहीं छीना जाएगा, न ही उसकी सुरक्षा पर आ रही आंच को लेकर कोई चिंता जताई। क्योंकि प्रधानमंत्री खुद नहीं जानते कि जब असलियत में काम करना होता है, तो क्या और कैसे किया जाता है। श्री मोदी की इस कमजोरी को अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों समझ रहे हैं। नीतीश कुमार को तो फिर से मुख्यमंत्री बनने की लालसा है, लिहाजा है वो नरेन्द्र मोदी के सामने न केवल खुद हाथ जोड़ रहे हैं, बल्कि बार-बार बिहार की जनता से कह रहे हैं, उठो रे, इनका नमन करो, इनको प्रणाम करो। ऐसा करके नीतीश कुमार उस लोकतंत्र को थप्पड़ मारने का काम कर रहे हैं, जिसके बूते इन लोगों को सत्ता पर बैठने मिला है। भला ये कोई बात हुई कि जनता का काम करने के लिए चुने गए लोगों को इस बात के लिए प्रणाम किया जाए कि वो काम कर रहे हैं, और जो काम नहीं कर पाएं हैं, या नहीं कर रहे हैं, क्या उसके लिए इन्हीं लोगों से सवाल नहीं होने चाहिए। क्या नीतीश कुमार एक बार भी यह कहेंगे कि उठो रे पूछो इनसे कि मोतिहारी में चीनी मिल चालू क्यों नहीं हुई है। खैर.. नीतीश कुमार कुछ न कहें या नरेन्द्र मोदी जनता के सवालों का जवाब न दे, फिर भी सवाल तो उठेंगे ही। इस मानसून सत्र में विपक्ष ऐसे ही सवालों को उठाने की तैयारी में है, जिनसे बचने की कोशिश में श्री मोदी कितनी बार संसद से गायब रहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र को लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। शनिवार शाम इस सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। हालांकि, इसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई, उसने बाकायदा कह दिया है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा तक ही था, लेकिन जो सवाल कांग्रेस समेत बाकी विपक्ष के हैं, वही सवाल आप के भी हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन के उठाए सवालों में आप की आवाज शामिल हो या न हो, उन सवालों के असर से मोदी बच नहीं सकते। इंडिया गठबंधन के सवाल कितने कठिन रहने वाले हैं, इसकी झलक शनिवार को राहुल के एक ट्वीट से मिल भी गई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर पर 24वीं बार किए गए दावे से एक बात को उठाते हुए राहुल ने सवाल किया है कि पांच जहाजों का सच क्या है। दरअसल ट्रंप ने इस बार पांच लड़ाकू जहाजों के नुकसान का भी जिक्र किया, लेकिन शायद जानबूझ कर ट्रंप ने यह नहीं बताया कि ये जहाज भारत के थे या पाकिस्तान के। भारत में पहले सीडीएस से लेकर इंडियन नेवी के अफसर तक ने यह बयान दिया है कि भारत को नुकसान हुआ है, लेकिन विपक्ष के पूछने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ट्रंप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनके बयान पर नरेन्द्र मोदी अपने देश में घिर रहे हैं, और लड़ाकू विमान के गिरने की बात पर भी उनसे सवाल हो सकते हैं, फिर भी शायद नरेन्द्र मोदी को फंसाने के लिए ट्रंप ने ऐसा उलझाने वाला बयान दिया, ताकि भ्रम फैले। संसद में अब समूचा विपक्ष इस पर सच की मांग करेगा। सरकार भले ऑपरेशन सिंदूर को देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला बताकर सवाल को रफा-दफा करे या फिर इसके लिए कुछ सांसदों को निलंबित करे या जब वो बोलने खड़े हों तो उनके माइक बंद कर दिए जाएं, लेकिन क्या अब जनता तक इन सवालों को पहुंचने से रोका जा सकता है। वैसे मानसून सत्र में कौन से मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे, इसे लेकर इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हुई, उसमें 24 दलों के नेता शामिल हुए। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के 24 बयान, बिहार में एसआईआर की कवायद, एससी, एसटी पर अत्याचार, परिसीमन, अहमदाबाद विमान हादसा इन मुद्दों पर खास तौर से सरकार को घेरने की तैयारी है।

यााददाश्त कमजोर होने के शुरूआती संकेत क्या हैं, कैसे करें पहचान

क्या आप भी बार-बार चीजें भूल जाते हैं? जैसे घर से निकलने के बाद यह सोचना कि गैस बंद की या नहीं या बार-बार दरवाजा लॉक किया कि नहीं- तो यह एक चेतावनी हो सकती है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है. थोड़ी-बहुत भूलने की आदत आम है, लेकिन अगर ये रोजमर्रा के कामों को प्रभावित करने लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. याददाश्त कमजोर होने की कई वजहें हो सकती हैं जैसे सही खानपान की कमी, नींद पूरी न होना, तनाव या फिर दवाइयों और ड्रग्स का अधिक सेवन.

कमजोर याददाश्त के लक्षणों में बार-बार जरूरी चीजें भूलना, किसी बात को तुरंत याद न कर पाना, एकाग्रता की कमी और जरूरी कामों में गलतियां होना शामिल हैं. यह बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों सभी को प्रभावित कर सकता है. बच्चों में यह पढ़ाई में परेशानी लाता है तो बड़ों के लिए नौकरी और रिश्तों पर भी असर डाल सकता है. बढ़ती उम्र में भी याददाश्त कमजोर हो सकती है क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाएं समय के साथ धीमी हो जाती हैं. इसके अलावा, नींद की कमी, तनाव, सिर पर चोट और थायरॉयड या अल्जाइमर जैसी बीमारियां भी इसकी वजह बन सकती हैं. दिल्ली के मैक्स अस्पताल में न्यूरोसर्जरी विभाग में डॉ दलजीत सिंह ने कमजोर याददाश्त होने के इन कारणों और लक्षणों के बारे में बताया है

कमजोर याददाश्त के कारण

कारणों की बात करें तो सबसे पहले आता है पोषण की कमी. दिमाग को चलाने के लिए कुछ जरूरी पोषक तत्व चाहिए होते हैं जो हमें संतुलित भोजन से मिलते हैं. तला-भुना, बहुत मीठा और बहुत मसालेदार खाना दिमाग की सेहत को बिगाड़ता है.

1) एकाग्रता की कमी- जब मन कई चीजों में उलझा हो, तो दिमाग ठीक से कोई बात पकड़ नहीं पाता. बार-बार सोच का बिखराव हमारी याददाश्त पर असर डालता है.

2) सही पोषण की कमी- दिमाग को भी खाने से ताकत मिलती है. अगर शरीर में विटामिन इ12, ओमेगा-3 फैटी एसिड, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्वों की कमी हो जाए, तो याददाश्त कमजोर होने लगती है.

3) नींद पूरी न होना- दिमाग को आराम चाहिए. जब नींद पूरी नहीं होती तो दिमाग दिनभर की बातों को अच्छे से याद नहीं रख पाता, जिससे भूलने की दिक्कत बढ़ती है. इससे ब्रेन में केमिकल इंबैलेंस होने का रिस्क रहता है जो याददाश्त को प्रभावित करता है.

4) तनाव और चिंता- लगातार टेंशन लेने से दिमाग पर बोझ बढ़ता है. इससे दिमाग चीजों को याद रखने या पुराने यादों को वापस लाने में कमजोर हो जाता है.

5) उम्र का असर- जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे मस्तिष्क की कोशिकाएं धीमा काम करने लगती हैं जिससे याददाश्त पर असर पड़ता है. यह उम्र का सामान्य प्रभाव हो सकता है.

बड़ी जीत है द रेजिस्टेंट फ्रंट का आतंकी संगठन घोषित

-ललित गर्ग-

पहलगाम में जब आतंकी हमले में निदोर्षों का रक्त बहा, आहें एवं चीखें गूंजी, जिसने न केवल देश एवं दुनिया को झकझोर दिया था, बल्कि यह संकेत भी दे दिया कि आतंकवाद की जड़ें अब भी जीवित हैं और उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और सीमा-पार समर्थन प्राप्त है। लेकिन इस बार एक बड़ा परिवर्तनकारी एवं प्रासंगिक कदम अमेरिका की ओर से सामने आया है, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की मुखौटा इकाई द रेजिस्टेंट फ्रंट (टीआरएफ) को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया, इस तरह टीआरएफ की पहचान और आतंक के विरुद्ध वैश्विक एकजुटता का नया अध्याय लिखा गया है। यह कदम केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि आतंक के विरुद्ध वैश्विक मंच पर एक रणनीतिक संदेश है कि अब छद्म युद्ध और पनपते आतंक के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही का युग आ गया है। अमेरिका का यह कदम भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं विदेश मंत्री एस जयशंकर के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास इस बात के द्योतक है कि आतंकवाद से निपटने के मोर्चे पर भारत सफल हो रहा है। अमेरिका के इस फैसले ने न सिर्फ टीआरएफ के आतंकी चेहरे से बेपर्दा किया है, बल्कि पाकिस्तान की उन नापाक हरकतों को भी बेनकाब कर दिया, जिन्हें वह खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताकर छिपाता आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे भारत-अमेरिका के बीच मजबूत आतंकवाद-रोधी सहयोग का प्रमाण बताया है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग की जरूरत पर बल दिया है।

टीआरएफ दिखने में एक स्थानीय कश्मीरी संगठन होने का भ्रम देता है, लेकिन असल में यह लश्कर-ए-तैयबा और उसके सरगना हाफिज सईद की पुरानी साजिश का नया चेहरा है। पाकिस्तान-समर्थित आतंकी संगठनों को नया नाम एवं नये रूप में प्रस्तुत करना पाक की एक साजिश एवं सोची-समझी रणनीति है, ताकि दुनिया के सामने वह अपने दामन को पाक-साफ दिखा सके। एक और विडम्बनापूर्ण स्थिति यह है कि पाक ने इसे इस तरह पेश किया जैसे यह कश्मीर का स्थानीय संगठन हो। यह जगजाहिर है कि कई बड़े आतंकी संगठन पाकिस्तान की धरती से संचालित किए जा रहे हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिद्दीन प्रमुख हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कई बार ये सवाल उठे और पाक को आतंक पोषित स्वीकार्य किया जाने लगा। उसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने रणनीति बदली और आतंकी संगठनों के नाम भी बदलने शुरू कर दिए। टीआरएफ इसका एक उदाहरण है। इसका गठन 2019 के अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद हुआ और इसका उद्देश्य भारत में आतंकी घटनाओं को ह्यस्वदेशी विद्रोहह्ल की आड़ में अंजाम देना है। पहलगाम हमला भारत के उस प्रयास को चुनौती देता है जो वह ह्यपर्यटन और विकास के माध्यम से कश्मीर को मुख्यधारा में लानेह्ल के लिए कर रहा है। जब भी कश्मीर में शांति की बहार आती है, ऐसे आतंकी संगठन हिंसा का तूफान लेकर आते हैं। टीआरएफ ने सोशल मीडिया, इंटरनेट और कूटनीतिक शब्दजाल का इस्तेमाल करके अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को ह्यकश्मीरी प्रतिरोध आंदोलनह्ल के रूप में पेश करने की कोशिश की, जबकि उसके तार रावलपिंडी और आईएसआई के आतंकवाद समर्थन तंत्र से सीधे जुड़े हैं। मगर, अमेरिका की ओर से इसे वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जाना इस बात का सबूत है कि आतंकियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के इरादों को किसी छद्म नाम की आड़ में छिपाया नहीं जा सकता।

अमेरिका द्वारा टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जाना भारत की एक बड़ी राजनयिक एवं कूटनीतिक सफलता है। यह दिखाता है कि भारत की तीक्ष्ण एवं ताकतवर विदेश नीति अब केवल घटनाओं की निंदा तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण की रणनीति पर आधारित है। जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्तावों को भी बल देती है। भारत पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध वर्षों से चेतावनी देते हुए दुनिया को आतंकमुक्त बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक स्तर पर विभिन्न देशों को आतंक के खिलाफ एकजुट करने के प्रयास तेज किये हैं। ऐसे में अमेरिका पर भी यह साबित करने का दबाव बना है कि वह आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड न अपनाये। क्योंकि अमेरिका का दोगलापन चर्चा में रहा है, एक तरफ अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का दावा करता है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और विश्व बैंक से बड़ी धनराशि कर्ज के रूप में दी जाती है। एक तरफ राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़े होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आतंकवाद की नर्सरी चलाने वाले पाकिस्तान को लेकर अपने नरम रुख का इजहार भी करते रहते हैं। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का ढुलमुल रवैया भी हैरान करने वाला है। सवाल यह है कि जब अमेरिका यह मानता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पाल-पोस रहा है, तो वह वैश्विक संस्थाओं से उसे वित्तीय मदद रोकने की वकालत क्यों नहीं करता है?

ऑपरेशन सिंदूर में पाक को करारी मात देने के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में वातावरण बनाने के लिये तत्पर हुआ। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती देने के लिये ही भारत ने अमरीका समेत 32 देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे थे। इन देशों को पुख्ता सबूतों के साथ बताया गया कि टीआरएफ पाकिस्तान प्रायोजित लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है। संभवतः भारत के यही प्रयास इस संगठन के खिलाफ अमरीका के सख्त फैसले का आधार बनी। अमरीका ने इससे पहले 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को आतंकी संगठन घोषित किया था। पाकिस्तान इन दोनों संगठनों की तरह टीआरएफ को भी भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। निश्चित ही अमेरिका की यह ताजा कार्रवाई स्वागतयोग्य है, लेकिन भारत को अब केवल प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कमर कसते हुए प्रक्रिया दिखानी चाहिए। उसे सीमा पार सर्जिकल/ड्रोन स्ट्राइक की नीति को और मजबूत करना चाहिए। आतंकी समर्थकों की फंडिंग रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों की मांग करनी चाहिए। घरेलू स्तर पर खुफिया तंत्र और साइबर निगरानी को और सक्रिय एवं आधुनिक बनाना चाहिए। वैश्विक मंचों पर एफएटीएफ, यूएन, और जी 20 जैसे संगठनों में पाकिस्तान की आतंक-समर्थक भूमिका को बार-बार उजागर करना चाहिए। आज आवश्यकता है कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक और शांति-प्रिय राष्ट्र एक मंच पर एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टोलरेंस पॉलिसी अपनाएं। किसी भी राष्ट्र को- चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, आतंकियों की शरणस्थली बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। टीआरएफ को आतंकवादी घोषित करना पहला कदम है, अब इसकी जड़ों को नष्ट करना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। पाकिस्तान सरकार, सेना और आतंक के नापाक गठजोड़ पर जब तक सभी देश एकमत नहीं होंगे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचेगी। सवाल यह भी है कि जब पाकिस्तान आतंकी संगठनों का खुलेआम समर्थन करता रहता है तो उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट में डालने से परहेज क्यों किया जा रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि अमरीका के ताजा कदम के बाद एफएटीएफ और दूसरी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां टीआरएफ की फंडिंग की जांच करेंगी।

पहलगाम का हमला एक बार फिर हमें चेतावनी देता है कि आतंकवाद केवल सुरक्षा का संकट नहीं, बल्कि सभ्यता, शांति और मानवता का अपमान है। हमें अब शब्दों से आगे बढ़कर संकल्प और कार्यवाही की ओर बढ़ना होगा। भारत को अब केवल प्रतिकार नहीं, बल्कि निर्णायक प्रहार की नीति अपनानी चाहिए ताकि अगली पीढ़ी एक ऐसे भारत में सांस ले सके जहां ह्यकश्मीरह्ल केवल खूबसूरती का पर्याय हो, आतंक का नहीं। भारत को वैश्विक मंचों पर टीआरएफ को बेनकाब करने की मुहिम जारी रखनी चाहिए, ताकि इस संगठन को फिर फन उठाने का मौका न मिले।

स्कूलों को उड़ाने की धमकियांः सुरक्षा पर मंडराता खतरा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करीब 45 स्कूलों में बम विस्फोट की धमकी बेहद गंभीर और चिंताजनक है। चूंकि ऐसी धमकियां लगातार आ रही हैं, इसलिए हमारे सुरक्षा तंत्र को बहुत सजग हो जाना चाहिए। यह पुलिस एवं प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती एवं गंभीर प्रश्न है, क्योंकि बीते कुछ ही दिनों में करीब चार बार ऐसी धमकियों के ई-मेल अथवा फोन से डराने एवं धमकाने वाले सन्देश मिले हैं। इसी बुधवार को ही सात स्कूलों को विस्फोट की धमकी मिली थी। अगर यह किसी की सोचा-समझी साजिश है तो बहुत गंभीर है। किसी की शरारत भी है, तब भी अक्षम्य अपराध है। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में स्कूलों को उड़ाने की मिल रही ऐसी धमकियां न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि यह हमारे भविष्य, यानी बच्चों की मानसिक शांति और शिक्षा के अधिकार पर भी गहरा आघात है। कई बार ये धमकियां फर्जी साबित हुईं, लेकिन हर बार छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में भारी दहशत का माहौल बना, जिससे न केवल शिक्षण प्रभावित हुआ बल्कि प्रशासन की सजगता और तत्परता भी सवालों के घेरे में आ गई।

मई 2024 में एक ही दिन में दिल्ली के 100 से अधिक स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं थी। राजधानी के प्रतिष्ठित स्कूलों जैसे पश्चिम विहार इलाके में रिचमंड ग्लोबल स्कूल और रोहिणी सेक्टर-3 स्थित अभिनव पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इनमें तीन कॉलेज शामिल हैं। डीपीएस, मदर्स इन्टरनेशनल, संस्कृति स्कूल आदि प्रतिष्ठित स्कूलों को इस भयावह

चक्रव्यूह में शामिल किया गया है। ताजा धमकियों में हो सकता है, जांच में कुछ भी चिंताजनक न मिले, पर ऐसी धमकी से तात्कालिक रूप से जो तनाव पैदा होता है, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ई-मेल से दी गई धमकी की जो भाषा है, उस पर अवश्य गौर करना चाहिए। पुलिस और प्रशासन की तत्काल प्रतिक्रिया एवं सतर्कता के चलते सुरक्षा के कदम उठाते हुए स्कूलों को खाली कराया गया, बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। हालांकि बाद में अधिकतर धमकियां फर्जी ही पाई गईं, लेकिन जिस प्रकार बार-बार ये घटनाएं हो रही हैं, वह एक सुनियोजित मानसिक आतंकवाद की ओर इशारा करती हैं। इसमें मुख्यतः साइबर सुरक्षा में चूक भी दिख रही है।

इन डराने एवं खौफ पैदा करने वाली घटनाओं की अभी तक की जांच में पुलिस ने पाया है कि ये सभी धमकी भरे संदेश फर्जी हैं। फर्जी होने के बावजूद जांच को एक पुख्ता एवं सटीक समाधान तक पहुंचाना चाहिए। कौन अपराधी है, जो ऐसी धमकियां दे रहा है? अगर वह कोई बिगड़ैल बच्चा भी है, तो उसे इलाज की जरूरत है। वैसे इतने सुनियोजित तरीके की भेजी जा रही धमकियां किसी बिगडैल एवं शरारती बच्चे की नहीं हो सकती, जरूर इसके पीछे किसी बड़े षडयंत्रधारी का हाथ है। धमकाने की यह परिपाटी या किसी को डराने का यह तरीका अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। अधिकांश ईमेल और धमकियां विदेशी सर्वरों से भेजी गई थीं-रूस, यूक्रेन जैसे देशों से। यह भारत की साइबर सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंग के माध्यम से की जा रही साजिशों की ओर संकेत करती है। यह संकट केवल सुरक्षा का नहीं, मानसिक आघात का है। हर धमकी के बाद छात्रों की परीक्षा, पढ़ाई, उपस्थिति और मनोवैज्ञानिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ा है। बच्चों के भीतर असुरक्षा, भय और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है, जो उनके समग्र विकास के लिए बेहद खतरनाक है। अभिभावक-समाज में भी गहरा असंतोष और चिंता व्याप्त है, जो सरकार और पुलिस प्रशासन पर भरोसे को कम कर रही है।

इन डराने एवं असुरक्षा का वातावरण पैदा करने वाली धमकियों के बावजूद स्कूल प्रशासन की यह सराहनीय बात है कि ज्यादातर स्कूल खुले रहे और सबने सावधानी से काम लिया। कहीं भी अफरा-तफरी नहीं होने दी गयी। फिर भी ऐसी धमकियों के मनोवैज्ञानिक एवं संवेदनशील असर को गहराई से समझने की जरूरत है। क्या ऐसी बार-बार मिल रही धमकियों से हम एक डरा हुआ समाज ही नहीं, बल्कि एक लापरवाह समाज भी बना रहे हैं? आज ऐसी धमकियों से हमें डर लग रहा है, लेकिन कल हो सकता है, ये धमकियां हमें लापरवाह बना दें। तब शरारती तत्व किसी बड़ी घातक एवं अनहोनी घटना को अंजाम दे देने में सफलता पा ले। जरूरत है स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ अस्थायी जांच और अलार्म तक सीमित न रहे। एक स्थायी और आधुनिक सुरक्षा फ्रेमवर्क लागू किया जाना चाहिए, जिसमें सीसीटीवी, बायोमैट्रिक एंट्री, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम आदि अनिवार्य हों। साथ ही, स्कूलों को अपने स्तर पर भी पुख्ता सुरक्षा के प्रबंध रखने चाहिए। बच्चों के आने और स्कूल तक पहुंचने के मार्ग खुले, चौड़े व स्पष्ट होने चाहिए। यह परखना चाहिए कि स्कूलों में अग्निशमन की व्यवस्था है या नहीं? इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कूल सुरक्षित है या नहीं? अलार्म और निगरानी व्यवस्था चौकस है या नहीं? जो स्कूल टूटे-फूटे हुए हैं, जिन स्कूलों में जल भराव या फिसलन की समस्या है, वहां विशेष रूप से उपाय करने की जरूरत है।

इस तरह की धमकी देने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। आईटी एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत त्वरित कार्यवाही से ही ऐसे अपराधियों को रोका जा सकता है। धमकियां झूठी भी हों, तो भी दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि सभी को सबक मिले। यह अच्छी बात है कि दिल्ली के अनेक स्कूलों ने अपने विद्यार्थियों को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित कर रखा है। शुक्रवार को जब धमकी की बात सामने आई, तब भी अनेक स्कूलों में कक्षाओं को बहुत आसानी से खाली करा लिया गया। सारे विद्यार्थी अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए। वास्तव में, यह एक अनिवार्यता है कि सभी स्कूल अपने विद्यार्थियों को समय-समय पर प्रशिक्षित करें और मानसिक रूप से मजबूत रखें एवं ऐसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दें। स्कूलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श की व्यवस्था हो ताकि ऐसे हादसों से बच्चों और शिक्षकों पर पड़ने वाले मानसिक दुष्प्रभावों को कम किया जा सके।

बार-बार मिल रही इन धमकियों ने परिवारों में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता में डाल दिया है और लोग सरकार से यह उम्मीद कर रहे हैं कि वह इन धमकियों की तह में जाकर ठोस समाधान करें। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह बड़ा मौका है कि वे अपनी योग्यता प्रमाणित करें।

इतिहास से छेड़छाड़ में देश का नुकसान

एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की नई किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन काल की नयी तस्वीर पेश की गई है। इसके जरिए विद्यार्थियों को समझाया जा रहा है कि यह इतिहास का अंधेरा दौर था। किताब में बाकायदा एक अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर दिया गया है, जिसमें लिखा है कि 'इतिहास के अंधेरे दौर' के लिए आज किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। यह अस्वीकरण काफी अहमकाना लगता है, क्योंकि इतिहास और वह भी सदियों पुराने इतिहास के लिए तो यूं भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जो कुछ अतीत में घटा है, उसका तार्किक विश्लेषण करना, और गलतियों को न दोहराने का सबक लेना, इस मकसद के साथ इतिहास का पाठ किया जाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब इतिहास को संतुलित और संवेदनशील तरीके से पढ़ाया जाए। - संघ का शिक्षा एजेंडा : न पढ़ेंगे न पढ़ने देंगे इतिहास इस अर्थ में जटिल होता है कि वहां अच्छे और बुरे, सही और गलत का सीधा विभाजन नहीं होता, इनके बीच कई ऐसे मुकाम होते हैं, जहां हालात घटनाओं की व्याख्या करते हैं। कभी कोई राजा अपना राज्य बचाने के लिए क्रूरता का सहारा लेता है और कभी किसी राजा की अकर्मण्यहीनता में प्रजा पिसती है। हिंसा, रक्तपात, कत्लेआम, इंसानों की सामान की तरह तिजारत ऐसी कई अमानवीय घटनाएं भारत समेत पूरे विश्व इतिहास में दर्ज हैं। खासकर मध्ययुग का इतिहास तो इन्हीं से अटा पड़ा है, क्योंकि तब तक इंसान ने सभ्यता और विकास के मायने समझ लिए थे। आग और पहिए के आविष्कार के बाद अन्य पशुओं से आगे इंसान निकल गया तो उसके जीवन में व्यापार, धर्म और सियासत के लिए जगह बनने लगी। उस दौर में न कोई संविधान था, न आज की तरह का लोकतंत्र था, इसलिए नैतिकता के मापदंड भी अलग थे। तब की घटनाओं की व्याख्या आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं की जा सकती। मगर मोदी सरकार इस काम को भी मुमकिन बनाने में लगी है। दरअसल 2014 के बाद इतिहास के पुनर्लेखन पर ऐलानिया काम शुरू हो चुका है। इससे पहले जब भाजपा विपक्ष में थी, या उससे पहले जब बाजपेयी सरकार थी, तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच के मुताबिक ही भारतीय इतिहास का भगवाकरण करने की चाह भाजपा की रही, लेकिन उसे अमल में लाने का दुस्साहस कभी नहीं हुआ। अब चूंकि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो भाजपा को यह गुमान है कि उसकी सत्ता भारत में स्थायी हो चुकी है, इसलिए अब इतिहास को बदलने पर काम शुरू हो गया है। एनसीईआरटी की किताबों को इसका जरिया बनाया गया है। क्योंकि इसके जरिए नयी पीढ़ी के दिमाग में जहर बोने का काम आसानी से होगा। कोई आरोप लगाए तो उसे किताब का डिस्क्लेमर दिखाया जाएगा। 2025-26 सत्र के लिए प्रकाशित की गयी कक्षा 8 की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड (भाग 1) में बाबर, अकबर, औरंगजेब सभी को बेहद क्रूर, निर्दयी शासकों की तरह पेश किया गया है, जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, उन पर जजिया कर लगाया और औरतों-बच्चों को बेरहमी से मारा। इसलिए इस पूरे काल के लिए अंधेरे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस अंधेरे दौर में ही रामचरित मानस लिखी गई और इसी दौर में विश्वप्रसिद्ध ताजमहल भी बना, जिसे देखने दुनिया भर के सैलानी आज भी आते हैं। भूमि की नापजोख से लेकर राग रागिनियों की रचना, खान-पान, पोशाकों पर प्रयोग सब इसी दौर में हुए। सबसे बड़ी बात यह कि जिस अंधेरे दौर का जिक्र कर मुगल शासकों पर आततायी होने का इल्जाम लगाया जा रहा है, और हिंदुओं के लिए उसे खतरे की तरह बताया जा रहा है, उस काल के गुजरने के बाद भी देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं और मुस्लिम अल्पसंख्यक। 1526 से लेकर 1857 तक मुगलकाल 331 साल तक चला, इतने लंबे वक्त में तो भारतीय समाज की धार्मिक पहचान आसानी से बदल सकती थी। जैसा कि किताब में दावा है कि जजिया 'अपमानजनक कर' था, जो गैर-मुस्लिमों पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से लगाया जाता था। इस किताब में मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ने का इल्जाम भी मुगल शासकों पर लगा। यह सब सौ फीसदी सच होता तो देश में न चार-पांच सौ साल पुराने मंदिर बचे होते, न हिंदुओं की आबादी मुस्लिमों से अधिक होती। दरअसल जो कुछ किताब में लिखा है, वह तस्वीर का एक ही पहलू है। अह्लरङ्ग फर्मी - सड़क निर्माण करवाने की अनोखी कहानी इसमें कोई दो राय नहीं कि अकबर ने युद्ध नहीं किए या औरंगजेब ने मंदिरों को नष्ट नहीं किया। लेकिन औरंगजेब ने मंदिरों को दान भी दिए और अकबर ने जजिया कर को खत्म किया,

इसके बाद धार्मिक एकता और सहिष्णुता बढ़ाने के लिए सुलह कुल नीति चलायी, जिसकी तारीफ खुद छत्रपति शिवाजी ने की है। उन्होंने लिखा कि अकबर ने 52 साल तक सभी समुदायों—ईसाई, ब्राह्मण, जैन, सिख—पर समान कृपा बरसाई, जिसके कारण उन्हें 'जगतगुरु' कहा गया।

निर्दोषों की हत्या करने वालों को छूट नहीं, सजा मिलेगीः अमेरिका

एजेंसी

वाशिंगटन । अमेरिकी हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स ने द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) घोषित करने के फैसले का समर्थन किया है। कमेटी ने कहा कि इस संगठन के हिंसक कृत्यों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा होनी चाहिए और दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए। कमेटी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे सही कहा है। द रेसिस्टेंस फ्रंट एक आतंकवादी संगठन है और इसे यह दर्जा मिलना ही चाहिए। जो लोग निर्दोष नागरिकों की हत्या करते हैं, उन्हें छूट नहीं मिलती, बल्कि उन्हें न्याय का सामना करना पड़ता है। यह बयान अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) घोषित करने के बाद आया है। टीआरएफ, पाकिस्तान-आधारित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का एक सहयोगी संगठन है। इसने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। यह 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला था। विदेश विभाग ने कहा कि यह कदम ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभाग ने कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रपति ट्रंप के पहलगाम हमले के लिए न्याय की मांग को लागू करने का हिस्सा है।

चीन ने तिब्बत में दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना का निर्माण शुरू किया

बीजिंग। चीन ने भारत की चिंताओं को दरकिनार करते हुए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में यारलुंग सांगपो नदी के निचले इलाकों में लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन (167.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) लागत वाली जलविद्युत परियोजना का निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। चीनी परिषद ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। परिषद के बयान में कहा गया है 'चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने यारलुंग ज़ंगबो नदी के निचले इलाकों में एक जलविद्युत परियोजना के निर्माण की शुरुआत की घोषणा की।' इस परियोजना में पाँच (सीढ़ीदार)कैस्केड जलविद्युत संयंत्र शामिल होंगे, जिनकी कुल लागत लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन (लगभग 167.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) होने का अनुमान है। इस परियोजना से बनने वाली बिजली का इस्तेमाल मुख्य रूप से बाहरी खपत के साथ-साथ तिब्बत में स्थानीय मांग लिए भी किया जाएगा। इस जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य चाइना याजियांग ग्रुप कंपनी कर रही है जो परियोजना के पूरा होने के बाद इसका संचालन भी करेगी। इस समय दुनिया का सबसे बड़ा जलविद्युत संयंत्र मध्य चीन के हुबेई प्रांत में यांग्त्ज़ी नदी पर स्थित सैंक्सिया (तीन घाटियाँ) माना जाता है।

इजरायल ने हमास के शीर्ष हथियार कमांडर को किया ढेर, गाजा में 75 आतंकी ठिकानों पर भीषण हमला

गाजा/यरुशलम। इजरायल रक्षा बलों ने आज, 21 जुलाई 2025 को गाजा पट्टी में हमास के एक शीर्ष हथियार कमांडर को सटीक हवाई हमले में मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ ने बताया कि मारे गए कमांडर की पहचान हमास की हथियार निर्माण और तस्करी इकाई के प्रमुख के रूप में की गई है, जो इजरायल के खिलाफ रॉकेट और अन्य हथियारों के उत्पादन और आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इस कार्रवाई को हमास की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस हमले के साथ ही, इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के 75 से अधिक आतंकी ठिकानों पर भारी हवाई हमले किए हैं। इन ठिकानों में रॉकेट लॉन्चपैड, हथियार डिपो, कमांड सेंटर और भूमिगत सुरंगें शामिल हैं, जिनका उपयोग आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता था। आईडीएफ के अनुसार, ये हमले हमास द्वारा इजरायली नागरिकों पर किए जा रहे लगातार रॉकेट हमलों के जवाब में किए गए हैं। गाजा में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और दोनों पक्षों के बीच हिंसा बढ़ने की आशंका है, जिससे क्षेत्र में स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

पश्चिम देश रोमानिया को हस्तक्षेप के लिए आधार बना रहे हैं , रूसी राजनयिक का दावा

मॉस्को/बुखारेस्ट। बुखारेस्ट में रूस के राजदूत व्लादिमीर लिपायेव ने कहा है कि रोमानिया में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) सैनिकों की बढ़ती उपस्थिति के बीच पश्चिमी शक्तियां रूस-यूक्रेन युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए रोमानिया का इस्तेमाल एक आधार के रूप में कर रही हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ रहा है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी आरआईए नोवोस्ती से बात करते हुए श्री लिपायेव ने कहा, यह स्पष्ट है कि तथाकथित सामूहिक रूप से पश्चिम के देश अपनी सशस्त्र सेनाओं का सीधे उपयोग किए बिना यूक्रेन में संघर्ष में लगातार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, और तनाव को बढ़ाकर इसके रुख को बदलने की उम्मीद कर रहे हैं। राजनयिक ने बताया कि देश के क्षेत्र में अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली के तत्व तैनात किए गए हैं, सैन्य ठिकानों का विस्तार किया जा रहा है, और नाटो की टुकड़ी बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि मिहाई कोगलनिसेनु एयरबेस सेवस्तोपोल से 400 किमी से भी कम दूरी पर स्थित है। उन्होंने कहा, वर्ष 2016 से अमेरिकी एजिस एशोर मिसाइल रक्षा प्रणाली को देवेसेलु गाँव के क्षेत्र में तैनात किया गया है।

खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में 17 आतंकी मारे गए, आठ गिरफ्तार

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुरक्षाबलों ने मुल्क के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में 17 आतंकवादियों को मार गिराया। इस दौरान आठ दहशतगर्दों को दबोच लिया। यह जानकारी इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) और खुफिया सूत्रों ने दी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, आईएसपीआर ने रविवार देरशाम बताया कि 16 से 20 जुलाई तक खैबर-पख्तूनख्वा (केपी) के मलकंद जिले में एक संयुक्त खुफिया-आधारित अभियान चलाया गया। इस दौरान नौ आतंकवादी मारे गए और आठ अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सभी फितना अल-ख्वारिज से जुड़े हैं।

12 बस यात्रियों की हत्या

आईएसपीआर ने बताया कि आतंकवादियों के दो ठिकानों को नष्ट

कर दिया गया। इस दौरान हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया। इस बीच सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान प्रांत में दो अलग-अलग खुफिया आधारित अभियानों में आठ आतंकवादियों को मार गिराया। बताया गया है कि इससे पहले कलात जिले में नीमुर्ग क्रॉस के पास कराची से क्वेटा जा रही एक यात्री बोगी पर गोलीबारी में कम से कम तीन यात्रियों की मौत हो गई और सात घायल हो गए। एक अन्य आतंकी हमले में लोरलाई जिले में बसों से नौ यात्रियों का अपहरण कर उन्हें मार डाला गया। डान अखबार की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस अभियान में सफलता के लिए सुरक्षा बलों और सेना की सराहना की है। एक अन्य घटनाक्रम में ऊपरी दक्षिण वजीरिस्तान जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में एक संदिग्ध क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमले में एक महिला की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। इस बीच ऊपरी दक्षिणी वज़ीरिस्तान में दो अलग-अलग घटनाओं में एक सब-इंस्पेक्टर समेत सात पुलिस कर्मचारियों का अपहरण कर लिए जाने की खबर है।

सड़क पर चलती कार पर गिरा बड़ा पत्थर, आगरा के तीन युवक घायल

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल घूमने आए भारत के आगरा शहर (यूपी) के तीन युवक उस वक्त घायल हो गए, जब रविवार की दोपहर को उनकी कार पर पहाड़ से अचानक ही एक बड़ा पत्थर गिर गया। नारायणघाट मुगलिंग राजमार्ग से काठमांडू के तरफा रही (यूपी 80 जीपी 2928) कार पर भूस्खलन के कारण पहाड़ से एक बड़ा पत्थर कार के अगले हिस्से पर आ गिरा, जिसके कारण उसमें सवार तीनों भारतीय युवक घायल हो गए हैं।

चितवन जिला पुलिस के डीएसपी रविन्द्र खनाल ने कहा कि कार में सवार आगरा (यूपी) के रहने वाले 42 वर्षीय रतेंद्र यादव, 33 वर्षीय हरमन यादव और 33 वर्षीय हितेंद्र यादव घायल हो गए हैं। तीनों घायलों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।

गाजा में मदद के लिए जुटे 85 फिलीस्तीनियों की मौत, इजराइल ने व्यापक निकासी आदेश जारी किए

एजेंसी

दीर अल-बलाह। गाजा में मानवीय सहायता की तलाश कर रहे कम से कम 85 फिलीस्तीनियों की गोलीबारी में मौत हो गई, जो पिछले 21 महीनों में सहायता पाने वालों के लिए सबसे घातक दिन रहा। गाजा की स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। इस घटना के बीच इजराइल की सेना ने केंद्रीय गाजा के कई हिस्सों में नए निकासी आदेश जारी किए हैं। यह क्षेत्र अब तक जमीन पर सैन्य अभियान से अपेक्षाकृत अछूता रहा था और जहां कई अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियां कार्यरत हैं। रिपोर्टों के अनुसार, कई संगठनों को तत्काल अपने कार्यालय खाली करने के लिए कहा गया है। उत्तरी गाजा, जो भारी तबाही और भुखमरी से जूझ रहा है, वहां ज़िकिम क्रॉसिंग के पास सहायता के लिए जुटे लोगों पर गोलीबारी में कम से कम 79 फिलीस्तीनी मारे गए। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकॉर्ड विभाग प्रमुख ज़ाहर अल-वाहेदी ने बताया कि इस समय संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के 25 ट्रक वहां भूख से

बेहाल समुदायों के लिए मदद लेकर पहुंचे थे, तभी भारी भीड़ जमा हो गई। ईहाब अल-ज़ेई, जो आटा लेने पहुंचे थे, ने बताया, अचानक चारों ओर टैंक आ गए और गोलियों और हमलों के बीच हम दो घंटे तक फंसे रहे। अब मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। भूख से मरना बेहतर है। एक अन्य घायल नागरिक नाफिज अल-नज्जार ने कहा कि टैंकों और ड्रोन ने लोगों को बेतरतीब तरीके से निशाना बनाया, और उन्होंने अपने चचेरे भाई को मरते देखा। वहीं, इजराइली सेना ने बयान जारी कर कहा कि उत्तरी गाजा में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो सुरक्षा के लिए खतरा थी, और इसी वजह से सैनिकों ने फायरिंग की। सेना ने यह स्वीकार किया कि कुछ लोग हताहत हुए हैं, लेकिन गाजा के अधिकारियों द्वारा बताए गए आंकड़ों को उसने अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बताया। साथ ही, उसने हमास पर जानबूझकर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया।

रूस ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता की जताई इच्छा, लेकिन लक्ष्यों से पीछे हटने से इनकार

एजेंसी

मॉस्को। रूस ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार होने की बात कही है, साथ ही यह स्पष्ट भी किया है कि वह अपने घोषित लक्ष्यों से किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगा। यह बयान क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस को 50 दिनों की समयसीमा दिए जाने के कुछ ही दिन बाद दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर इस समय सीमा के भीतर युद्धविराम पर सहमति नहीं बनी तो रूस को और कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। पेस्कोव ने एक सरकारी टेलीविजन चैनल से बातचीत में कहा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार यह कह चुके हैं कि वह यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। लेकिन यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए प्रयास और समय की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपने लक्ष्यों को हासिल करना है। हमारे लक्ष्य

बिल्कुल स्पष्ट हैं। रूस का स्पष्ट रुख है कि किसी भी शांति समझौते के लिए यूक्रेन को उन चार क्षेत्रों (डोनेत्स्क, लुहान्स्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसॉन) से पूरी तरह पीछे हटना होगा, जिन्हें रूस ने सितंबर 2022 में अवैध रूप से अपना हिस्सा घोषित किया था। हालांकि इन पर उसका पूर्ण नियंत्रण अब तक नहीं हो सका है। साथ ही, रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिशों को त्यागे और अपनी सैन्य क्षमता पर सख्त सीमाएं स्वीकार करे। ये सारी शर्तें अब तक कीव और पश्चिमी देशों द्वारा सिरे से खारिज की जा चुकी हैं।

जापान में उच्च सदन के चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन का खराब प्रदर्शन

एजेंसी

टोक्यो। जापान का सत्तारूढ़ गठबंधन संसद के उच्च सदन डायट के लिए हुए चुनाव में पिछड़ता नजर आ रहा है। जापान के प्रमुख अखबार असाही शिंबुन के एग्जिट पोल के अनुसार, सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) का प्रदर्शन इस बार दमदार नहीं रहा। सरकारी प्रसारक एनएचके टेलीविजन का भी कुछ ऐसा ही दावा है। एनकेएच ने ऊपरी सदन में सत्तारूढ़ गठबंधन की सीटें कम होने का अनुमान जताया है। एनकेएच के अनुसार, इस चुनाव में धुर-दक्षिणपंथी सैनसेतो पार्टी ताकत के रूप में उभरी है। एनएचके में प्रसारित एक्जिट पोल में इशिबा के गठबंधन को 32-51 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। अन्य चैनलों के

मुताबिक इस गठबंधन को 40-43 सीट मिल सकती हैं। एलडीपी को अकेले 32 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। एलडीपी अभी भी संसद में सबसे बड़ी पार्टी है। एनएचके के अनुसार, मुख्य विपक्षी दल कान्स्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी को 18 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। पहले उसे 22 सीटें मिली थीं।धुर दक्षिणपंथी सैनसेतो पार्टी अपने जापानी फर्स्ट%अभियान की वजह से मतदाताओं को प्रभावित कर रही है। इस पार्टी को 10-22 सीटें मिलने की संभावना है। इसे पिछले चुनाव में एक सीट मिली थी। इस पार्टी की शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान यू-ट्यूब के जरिये हुई थी। अल्पमत की सरकार चला रहे प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन की सीटें कम होने से जापान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। हालांकि इस चुनाव से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री इशिबा की सरकार पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उच्च सदन में झटका लगने से उन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ सकता। महत्वपूर्ण यह है कि अक्टूबर में हुए निचले सदन के चुनाव में भी इशिबा की पार्टी का प्रदर्शन 15 वर्षों में सबसे खराब रहा था। उन पर अविश्वास प्रस्ताव का खतरा भी मंडरा रहा है। द जापान टाइम्स की खबर के अनुसार, सत्तारूढ़ गठबंधन उच्च सदन में अपना बहुमत खो सकता है। इस चुनाव को प्रधानमंत्री और एलडीपी के लिए करारा झटका माना जा रहा है। इशिबा ने रविवार देररात सरकारी प्रसारक एनएचके से कहा कि वह फिलहाल सरकार में बने रहेंगे।

नेपाल पीएमओ का दावा- 16 और 17 सितंबर को ओली करेंगे दिल्ली का दौरा

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 16-17 सितंबर को दो दिनों की दिल्ली यात्रा पर जायेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ओली का दिल्ली भ्रमण तय हो गया है और वो दो दिनों के दौरे पर 16 सितंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। बयान में कहा गया है कि यह दौरा भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर होने वाला है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को सत्ता संभाले एक वर्ष पूरा हो गया है, लेकिन अब तक उनका भारत भ्रमण नहीं होने के कारण देश के भीतर उनकी काफी आलोचना हो रही है। इसको देखते हुए भारत से भ्रमण के औपचारिक निमंत्रण को बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हालांकि, इस विषय पर काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास और दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के अधिकारियों का कहना है कि भ्रमण की बात चल रही है, पर तारीख तय होने की जानकारी उनके पास अभी तक नहीं आई है।

रूस के कामचटका तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी अलर्ट वापस लिया गया

एजेंसी

मॉस्को/कामचटका। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचटका के तट के पास 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया। हालांकि प्रारंभिक रूप से सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद इसे वापस ले लिया गया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (जीएफजेड) के अनुसार, यह भूकंप कामचटका के पूर्वी तट के पास 10 किलोमीटर की गहराई में आया। प्रारंभ में इसकी तीव्रता 6.7 मापी गई थी, जिसे बाद में संशोधित कर 7.4 कर दिया गया। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर (ईएमएससी) ने भी भूकंप की तीव्रता 7.4 बताई है। भूकंप के बाद अमेरिकी राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने हवाई राज्य के लिए सुनामी की निगरानी चेतावनी जारी की थी, जिसे जल्द ही रद्द कर दिया गया।

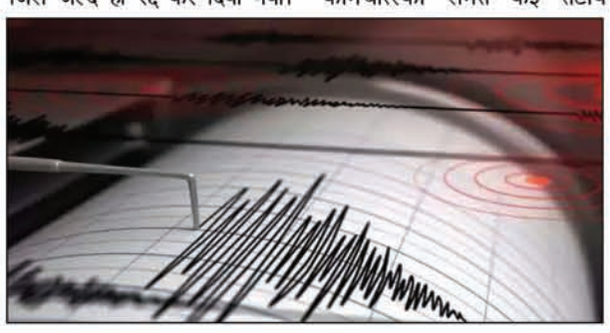

रूसी समाचार एजेंसी टास ने स्थानीय आपातकालीन सेवाओं के हवाले से बताया कि कामचटका क्षेत्र के लिए जारी सुनामी चेतावनी भी अब हटा ली गई है। इससे पहले, राजधानी पेट्रोपावलोव्स्क-कामचात्स्की समेत कई तटीय इलाकों में 60 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें उठने की संभावना जताई गई थी। हालांकि, अब तक किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन भूकंप के झटकों के चलते स्थानीय लोगों में घबराहट देखी गई। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आपातकालीन टीमें अलर्ट पर हैं।उल्लेखनीय है कि कामचटका क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र माना जाता है और यहां समय-समय पर तेज भूकंप आते रहते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र में इतनी कम गहराई पर आया यह भूकंप और भी गंभीर स्थिति पैदा कर सकता था, यदि समय रहते चेतावनियां जारी न की जातीं। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, लेकिन अधिकारियों ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

बांग्लादेश अगले पांच वर्षों तक अमेरिका से हर साल 7 लाख टन गेहूं का आयात करेगा

एजेंसी

ढाका। बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वह अगले पांच वर्षों तक हर साल 7 लाख टन गेहूं का आयात करेगा। यह समझौता ऐसे समय हुआ है, जब अमेरिका 01 अगस्त से बांग्लादेशी निर्यात पर 35 प्रतिशत टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। ढाका में बांग्लादेश के खाद्य मंत्रालय और अमेरिकी व्यापार संगठन 'यूएस व्हीट एसोसिएट्स' के बीच हुए इस समझौते को एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जो व्यापार तनाव को कम करने और अमेरिका के साथ आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। बांग्लादेश के कार्यवाहक खाद्य मंत्री अली इमाम मजुमदार ने समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान कहा, यह करार हमें उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं प्रतिस्पर्धी दरों पर सुनिश्चित करेगा और अमेरिका के साथ हमारे व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेगा। यह हमारे आपसी विश्वास को बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग को गहराई देने की हमारी मंशा को दर्शाता है। बांग्लादेश को उम्मीद है कि यह पहल अमेरिका के साथ उसके 06 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने में मदद करेगी और खासकर परिधान उद्योग जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को अमेरिका में बेहतर बाजार पहुंच दिलाने की राह खोलेगी। अमेरिकी टैरिफ वृद्धि ने बांग्लादेश के निर्यात उद्योग, विशेष रूप से रेडीमेड गारमेंट्स क्षेत्र में चिंता की लहर पैदा कर दी है, क्योंकि यह क्षेत्र अमेरिकी बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खोने से डर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका के साथ टैरिफ में राहत को लेकर वार्ता जारी है। उन्होंने तर्क दिया कि इतनी ऊंची दरें बांग्लादेश के निर्यातकों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश हर साल करीब 70 लाख टन गेहूं आयात करता है, जिसमें से अधिकांश सस्ती दरों के कारण ब्लैक सी क्षेत्र (रूस, यूक्रेन आदि) से आता है। अमेरिका से अब तक सीमित मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं मिलाकर उपयोग किया जाता रहा है।

पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस

एजेंसी

सियोल । दक्षिण कोरिया के विशेष जांच दल ने चुनाव में हस्तक्षेप और अन्य अनियमितताओं के आरोपों को लेकर पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल और उनकी पत्नी (पूर्व प्रथम महिला) किम कीम ही को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। विशेष वकील मिन जूंग-की की टीम ने सियोल डिटेंशन सेंटर में बंद योन को 29 जुलाई सुबह 10 बजे बतौर आरोपी पेश होने का नोटिस भेजा है। यह जानकारी सहायक विशेष वकील मून होंग-जू ने सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में दी। वहीं, किम को भी 6 अगस्त सुबह 10 बजे पेश होने के लिए उनके निवास स्थान पर समन भेजा गया है। अधिकारियों के मुताबिक, किम पर दो अलग-अलग स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन (शेयर बाजार में हेरफेर) मामलों में संलिप्तता, एक तांत्रिक से महंगे उपहार लेने और चुनावी नामांकन में हस्तक्षेप करने के आरोप हैं। योन पर भी चुनावी नामांकन में हस्तक्षेप का आरोप है। इससे पहले, 19 जुलाई को योन को मार्शल लॉ को सीमित समय के लिए लागू करने को लेकर सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप में आरोपित किया गया था। यह उनकी गिरफ्तारी के साथ तीसरी बार आरोपित किया जाना था। इससे पहले जनवरी और मार्च में भी उन्हें मार्शल लॉ और अन्य दुरुपयोग मामलों में आरोपित किया गया था। विशेष वकील चो यूं-सुक के नेतृत्व वाली टीम के अनुसार, योन पर कैबिनेट सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन करने, मार्शल लॉ की घोषणा को पीछे की तारीख से तैयार करने और एन्क्रिप्टेड फोन से रिकॉर्ड हटवाने जैसे आरोप हैं।

ऑस्ट्रेलिया: मेलबर्न में चाकूबाजी, अलग-अलग घटनाओं में दो लोग घायल

एजेंसी

सिडनी । ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में शॉपिंग सेंटरों में 24 घंटे के भीतर चाकूबाजी की दो अलग-अलग घटनाओं में दो लोग घायल हो गए। गंभीर हालत में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार शाम लगभग 6:30 बजे, मेलबर्न से 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित ब्रॉडमेडोज उपनगर के एक शॉपिंग सेंटर में चाकूबाजी की घटना सामने आई। एक पीड़ित को चाकू के घाव के साथ पाया गया, जिसके बाद आपातकालीन सेवाओं को तुरंत बुलाया गया। पुलिस ने उसकी पहचान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया के अखबारों ने बताया है कि पीड़ित 17 वर्षीय लड़का था।

गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने से पहले उसका घटनास्थल पर ही इलाज किया गया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, शनिवार रात एक अलग घटना में, मेलबर्न के पश्चिमी क्षेत्र में अल्टोना मीडोज के एक शॉपिंग सेंटर में 33 वर्षीय एक व्यक्ति पर लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया।

एक पुलिस प्रवक्ता ने न्यूज कॉर्प को बताया कि उस व्यक्ति के पास कुछ पुरुष

आए और उसे जमीन पर गिरा दिया, उसके बाद उसके हाथ पर धारदार हथियार से वार किया गया।उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके हाथ का निचला हिस्सा काट दिया गया। सोमवार तक, किसी भी हमले के संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। 15 जुलाई को इसी तरह की एक घटना में, मेलबर्न के एक शॉपिंग सेंटर के बाहर चाकू से हमले के बाद एक अन्य व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

विक्टोरिया राज्य की पुलिस ने बताया कि मध्य मेलबर्न से 7 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में मूनी पॉन्ड्स स्थित शॉपिंग सेंटर के बाहर पैदल चल रहे दो व्यक्तियों को बहस करते देखा गया, जिसके बाद एक व्यक्ति ने दूसरे पर चाकू से वार किया। 44 वर्षीय पीड़ित को गर्दन और सीने में चोटें आईं और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

55 वर्षीय कथित हमलावर को पुलिस के आने तक लोगों ने रोके रखा। उसे हिरासत में ले लिया गया और उस पर लापरवाही से चोट पहुंचाने, जानबूझकर हथियार से हमला करने का आरोप लगाया गया।

सेबी ने जून में 'स्कोर्स' पोर्टल पर लगभग 4,500 शिकायतों का समाधान किया

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जून में अपने ऑनलाइन शिकायत निवारण मंच 'स्कोर्स' के माध्यम से 4,415 शिकायतों का निपटारा किया है। सेबी ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि उसे जून में 4,959 नई शिकायतें प्राप्त हुईं और जून के अंत तक कुल 5,107 शिकायतें अनसुलझी रहीं। यह 31 मई तक लंबित 4,563 शिकायतों से थोड़ी अधिक है। नियामक ने बताया कि जून में संस्थाओं द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने में लिया गया औसत समाधान समय आठ दिन था, जबकि प्रथम स्तरीय समीक्षा के तहत शिकायतों के लिए लिया गया औसत समय चार दिन था। स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) एक ऑनलाइन मंच है जो निवेशकों को सूचीबद्ध कंपनियों और पंजीकृत मध्यस्थों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और उन पर नजर रखने में सुविधा प्रदान करता है। स्कोर्स 2.0 प्रणाली के तहत, शिकायतें स्वचालित रूप से संबंधित संस्थाओं को भेज दी जाती हैं, जिन्हें 21 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। अगर कोई निवेशक संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास प्रथम स्तरीय समीक्षा के लिए 15 दिन का समय होता है। इसी प्रकार का समीक्षा अवसर दूसरे स्तर पर नामित निकाय के साथ तथा तत्पश्चात सेबी के साथ, प्रत्येक 15 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध है।

विकेन्द्रित सौर ऊर्जा में राजस्थान बन रहा देश का प्रमुख केंद्र

जयपुर। राजस्थान विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनकर उभरा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक साल में ही पीएम-कुसुम योजना के तहत 1,190 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है। एक बयान के अनुसार, राजस्थान में अब तक 1,305 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले कुल 684 विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 592 संयंत्र (1,190 मेगावाट) पिछले 12 महीनों में स्थापित किए गए हैं। बयान में कहा गया कि यह संयंत्र उद्योगपतियों अथवा बड़े वाणिज्यिक समूहों द्वारा नहीं बल्कि खुद किसानों द्वारा या किसी डेवलपर के साथ मिलकर खेत के समीप अपनी गैर-कृषि योग्य भूमि पर लगाए जा रहे हैं। इन सौर संयंत्रों के माध्यम से किसान अब ऊर्जादाता भी बन रहे हैं और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता के नए युग की शुरुआत हुई है। ये संयंत्र ग्रिड सबस्टेशन के पांच किलोमीटर के भीतर स्थापित किए जाते हैं और ताप विद्युत की तुलना में काफी कम दर यानी 2.09 रुपये से तीन रुपये प्रति यूनिट पर बिजली प्रदान करते हैं। इस योजना को अब स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण आजीविका के लिए एक दोहरे समाधान के रूप में देखा जा रहा है, जहां किसान बिजली उत्पादक बन रहे हैं, वहीं बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को कम लागत और कम नुकसान वाले वितरण का लाभ मिल रहा है।

सिग्नेचर ग्लोबल सितंबर तिमाही में गुरुग्राम में 6,000 करोड़ रुपये की आवासीय परियोजना पेश करेगी

नई दिल्ली। रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने अंतिम उपयोगकर्ताओं और निवेशकों की मांग को पूरा करने के लिए चालू तिमाही में गुरुग्राम में 6,000 करोड़ रुपये मूल्य के घरों की पेशकश की योजना बनाई है। सिग्नेचर ग्लोबल पिछले वित्त वर्ष (2024-25) में बिक्री बुकिंग के मामले में पांचवीं सबसे बड़ी सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनी थी। सिग्नेचर ग्लोबल से आगे गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, लोढ़ा समूह और प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड थीं। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 10,290 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री बुकिंग दर्ज की थी। विशेष बातचीत में, सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप कुमार अग्रवाल ने कहा कि कंपनी ने जून तिमाही के दौरान गुरुग्राम में एक आवासीय परियोजना शुरू की है, जिसकी कुल राजस्व क्षमता लगभग 3,500 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा, हम चालू तिमाही में 35-40 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली आवासीय परियोजना शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इसकी कुल बिक्री क्षमता लगभग 6,000 करोड़ रुपये होगी। अग्रवाल ने कहा कि मांग, खासकर अच्छे ब्रांड के लिए लगातार मजबूत बनी हुई है।

एनसीएलटी ने अदाणी सीमेंटेशन के अंबुजा सीमेंट्स के साथ विलय को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने अदाणी सीमेंटेशन और अंबुजा सीमेंट्स के विलय को मंजूरी दे दी है। अब अदाणी समूह के सीमेंट कारोबार को एक इकाई के अंतर्गत एकीकृत करने और सहक्रियात्मक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे पहले जून, 2024 में अरबपति गौतम अदाणी के नेतृत्व वाले समूह ने अपनी सीमेंट परिसंपत्तियों के विलय और स्वामित्व पुनर्गठन की घोषणा की थी, जो अंबुजा सीमेंट्स और अदाणी सीमेंटेशन के अंतर्गत हैं।अदाणी सीमेंटेशन, अदाणी एंटरप्राइजेज का हिस्सा है। एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ ने 18 जुलाई को एक आदेश पारित करते हुए अदाणी सीमेंटेशन और अंबुजा सीमेंट्स के विलय की योजना को मंजूरी दे दी। एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा, कंपनी की याचिका के अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न विलय योजना को मंजूरी दी जाती है और यह घोषित किया जाता है।

एंथेम बायोसाइंसेज ने निवेशकों को किया खुश, प्रीमियम लिस्टिंग के बाद लगा अपर सर्किट

एजेंसी

नई दिल्ली। बायोटेक फर्म्स और बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को सर्विस देने वाली कंपनी एंथेम बायोसाइंसेज के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मजबूत एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 570 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर इसकी एंट्री 723.10 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर 723.05 रुपये के स्तर पर एंट्री हुई। इस तरह एंट्री के साथ ही शेयरों को करीब 26 प्रतिशत का लिस्टिंग गेन मिल गया। लिस्टिंग के बाद शेयरों की लिवाली शुरू हो गई, जिसके कारण कुछ ही देर में कंपनी के शेयर उछल कर 734.82 रुपये के अपर सर्किट लेवल पर पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 28.91 प्रतिशत का मुनाफा हो गया। एंथेम बायोसाइंसेज का 3,395.79

करोड़ रुपये का आईपीओ 14 से 16 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जोरदार रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 67.42 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 192.80 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 44.70 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 5.98 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं एंप्लॉयीज के लिए रिजर्व पोर्शन में 6.99 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इस आईपीओ के तहत कोई नया शेयर जारी नहीं किया गया है, बल्कि 2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5,95,75,319 शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिए बेचे गए हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 385.19 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 367.31 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 451.26 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 30 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 1,930.29 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

बरेका के इंजनों की गूंज एक बार फिर विश्व पटल पर - मोजाम्बिक को 3300 एचपी डीजल लोकोमोटिव का सफल निर्यात

एजेंसी

नई दिल्ली। मेक इन इंडिया को वैश्विक ऊंचाई देने की दिशा में बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बरेका द्वारा निर्मित उन्नत 3300 अश्व शक्ति (एचपी) के केप गेज डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अब मोजाम्बिक की पटरियों पर दौड़ते नजर आएंगे। बरेका के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने बताया कि भारतीय रेलवे की इस प्रमुख निर्माण इकाई ने जून 2025 में ऐसे दो अत्याधुनिक लोकोमोटिव सफलतापूर्वक मोजाम्बिक के लिए रवाना किए हैं, जबकि शेष आठ इंजनों की आपूर्ति दिसंबर 2025 तक की जाएगी। यह पूरी आपूर्ति मेसर्स राइट्स के माध्यम से संपन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि 3300 एचपी के ये एसी डीजल इंजन तकनीक, मजबूती और विश्वसनीयता का अद्वितीय संगम हैं। इनमें अत्याधुनिक कर्षण प्रणाली, कंप्यूटर नियंत्रित ब्रेक सिस्टम (सीसीबी 2.0), अधिकतम कर्षण एफर्ट 400 किलो न्यूटन, सतत कर्षण एफर्ट 280 किलो न्यूटन, 6000 लीटर की ईंधन क्षमता और 100 किमी/घंटा की अधिकतम रफ्तार जैसी विशेषताएं मौजूद हैं।

चालक के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं: नरेश पाल सिंह ने बताया कि इन इंजनों में ड्राइवर की सुविधाओं और आराम का विशेष ध्यान रखा गया है। चालक कैब में रेफ्रिजरेटर, हॉट प्लेट, मोबाइल होल्डर, बोतल स्टैंड, सौंदर्यबोध से परिपूर्ण डिजाइन और शौचालय जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे न केवल कार्यस्थल की गुणवत्ता बेहतर होती है, बल्कि ये अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भी हैं। इन इंजनों के सुचारू संचालन के लिए मोजाम्बिक के 10 इंजीनियरों को भारत में तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

स्टॉक मार्केट में स्पनवेब की मजबूत एंट्री, लिस्टिंग के बाद लगा अपर सर्किट

एजेंसी

नई दिल्ली। नॉन वोवेन फैब्रिक बनाने वाली कंपनी स्पनवेब नॉनवोवेन के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 96 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 57.29 प्रतिशत प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग 151 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण कुछ ही देर में कंपनी के शेयर उछल कर 158.55 रुपये के अपर सर्किट लेवल पर पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 65.16 प्रतिशत का मुनाफा हो गया है। स्पनवेब नॉनवोवेन का 60.98 करोड़ रुपये का आईपीओ 14 से 16 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये

ओवरऑल 251.32 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 165.43 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 364.58 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 251.84 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 63,51,600 नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने, पुराने कर्ज को चुकाने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 1.13 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 5.44 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 10.79 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 38 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 227.14 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

होंडा-निसान मिलकर बनाएंगे कारों का डिजिटल ब्रेन, चीन की टेक्नोलॉजी को देंगे सीधी टक्कर

एजेंसी

नई दिल्ली। होंडा और निसान अब हार्डवेयर से हटकर कारों के भविष्य को 'स्मार्ट' सॉफ्टवेयर के जरिए रीडिफाइन करने जा रहे हैं। दोनों जापानी दिग्गज कंपनियां एक साथ मिलकर अगली पीढ़ी का कार सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यानी 'डिजिटल ब्रेन' तैयार करेंगी, जो चीन की तेजी से उभरती टेक कंपनियों जैसे क्व्ब्ह्ब्ष्, ह्द्बश और ङ्मश्चद्दठ्ठद् को चुनौती देगा। 10 अरब डॉलर से ज्यादा के निवेश के साथ यह साझेदारी बताती है कि अब ऑटोमोबाइल की लड़ाई इंजन नहीं, डेटा और डिजिटल इंटेलिजेंस से जीती जाएगी। होंडा और निसान के इस तकनीकी गठबंधन की सबसे खास बात इसका कॉमन सॉफ्टवेयर कोर है, जो दोनों कंपनियों की कारों को एक साझा डिजिटल रीढ़ पर आधारित करेगा। इसका मतलब है कि भले ही कारें अलग-अलग ब्रांड की हों, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर बेस एक जैसा होगा, जिससे विकास की लागत घटेगी और तकनीकी अपग्रेड में तेजी आएगी। यह गठबंधन केवल इंफोटेनमेंट सिस्टम यानी

म्यूजिक या स्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी कार का संचालन डिजिटल सिस्टम से होगा, जिसमें ड्राइविंग कंट्रोल, नेविगेशन, रियल टाइम अपडेट जैसी कई सुविधाएं शामिल होंगी। यानी सॉफ्टवेयर अब सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं, बल्कि वाहन की हर गतिविधि में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। इसके अलावा, दोनों कंपनियां डेटा के मालिकाना हक को अपने नियंत्रण में रखने की योजना बना रही हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी खुद की डेटा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगी और थर्ड पार्टी कंपनियों पर निर्भरता कम करेंगी। इससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि ग्राहकों की डेटा प्राइवेसी भी बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो सकेगी। गठबंधन की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि होंडा और निसान अब इलेक्ट्रिक मोटर्स और सेमीकंडक्टर जैसी महंगी तकनीकों को साझा करेंगी, जिससे न सिर्फ उत्पादन लागत घटेगी बल्कि नई तकनीकों के विकास में भी तेजी आएगी। कुल मिलाकर यह साझेदारी भविष्य की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने की ओर बड़ा कदम है।

सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में मामूली तेजी, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत में मामूली तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। सोना आज 100 रुपये से 110 रुपये प्रति 10 ग्राम तक उछल गया। इसके विपरीत चांदी की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीमत में उछाल आने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,00,150 रुपये से लेकर 1,00,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 91,800 रुपये से लेकर 91,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में बदलाव नहीं होने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज भी 1,16,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,00,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि

22 कैरेट सोने की कीमत 91,950 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,00,150 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 91,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,00,200 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 91,850 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,00,150 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 91,800 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,00,150 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 91,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,00,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 91,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 91,850 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,00,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 91,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जुलाई में किया 5,939 करोड़ रुपये का निवेश

एजेंसी

मुंबई। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जुलाई में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में 69.6 करोड़ डॉलर (5,939 करोड़ रुपये) का शुद्ध निवेश किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, महीने के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शेयरों में बिकवाली कर डेट खरीदे। इक्विटी में उन्होंने 64.3 करोड़ डॉलर की बिकवाली की जबकि 134.4 करोड़ डॉलर के डेट की लिवाली की। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में उन्होंने 4.6 करोड़ डॉलर

लगाये जबकि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट से पांच करोड़ डॉलर निकाले। इस महीने की शुरुआत में (एफपीआई) निवेशकों का रुख सकारात्मक था, हालांकि बाद में वे बिकवाल हो गये, खासकर पिछले सप्ताह। इससे पहले जून में एफपीआई निवेशक बिकवाल रहे थे। उन्होंने शुद्ध रूप से बाजार से 90.4 करोड़ डॉलर निकाले थे। पूरे कैलेंडर वर्ष के दौरान उन्होंने भारतीय पूंजी बाजार से 682.2 करोड़ डॉलर की शुद्ध निकासी की है।

साप्ताहिक समीक्षा : आईटी सेक्टर की सुस्ती ने लगातार तीसरे सप्ताह गिराया शेयर बाजार

जेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर बनी अनिश्चितता, विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली और आईटी सेक्टर की सुस्ती की वजह से घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुआ। खत्म हुए कारोबारी सप्ताह में बीएसई का सेंसेक्स 742.74 अंक यानी 0.90 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 81,757.73 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई के निफ्टी ने 181.45 अंक यानी 0.72 प्रतिशत की साप्ताहिक गिरावट के साथ 24,968.40 में अंक के स्तर पर पिछले सप्ताह के कारोबार का अंत किया। खत्म हुए कारोबारी सप्ताह के दौरान बीएसई के लार्जकैप इंडेक्स में 0.50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इस इंडेक्स में शामिल आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल

इंश्योरेंस कंपनी, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इंटरग्लोब एवियशन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एबीबी इंडिया और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टॉप लूजर्स की सूची में शामिल हुए। दूसरी ओर एचडीएफसी ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी, अदानी ग्रीन एनर्जी, वरुण बेवरेजेज, हीरो मोटोकॉर्प और बॉश के शेयर टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हुए। लार्जकैप इंडेक्स के विपरीत बीएसई के मिडकैप इंडेक्स में साप्ताहिक आधार पर एक प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। इस इंडेक्स में शामिल पीरामल एंटरप्राइजेज, अजंता फार्मास्यूटिकल्स, पतंजलि फूड्स, सोना बीएलडब्लू प्रेसीजन फोर्जिंग्स, थर्मैक्स, ग्लैंड फार्मास्यूटिकल्स, यूपीएल, बायोकॉन और गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर 6 से 14 प्रतिशत तक की साप्ताहिक मजबूती के साथ बंद हुए। बीएससी का स्मॉलकैप इंडेक्स पिछले सप्ताह के कारोबार के दौरान 1.50 प्रतिशत तक की मजबूती हासिल करने में सफल रहा। इस इंडेक्स में शामिल एलई ट्रैवेन्यू टेक्नोलॉजी, लागर्शी मोटर्स, जॉन कॉकेरिल इंडिया, नवकार कॉरपोरेशन, प्लैटिनम इंडस्ट्रीज, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, स्पोर्टकिंग इंडिया, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, आनंद राठी वेल्थ, गोदावरी बायो रिफाईनरीज, ऑल कार्गो टर्मिनल्स और आशापुरा माइन केम के शेयर 15 से 22 प्रतिशत तक की साप्ताहिक मजबूती के साथ बंद हुए।

दुबई और स्पेन यात्रा से मध्य प्रदेश को मिले 11 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव

एजेंसी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि उनकी दुबई और स्पेन की यात्रा मध्य प्रदेश में विकास के नए द्वार खोलेगी। दुबई और स्पेन के निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उत्साहित हैं। उनकी सात दिवसीय स्पेन और दुबई यात्रा मध्य प्रदेश को 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 14 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह जानकारी अपनी सात दिवसीय विदेश यात्रा से लौटने के बाद रविवार की रात भोपाल के राजा भोज विमानतल पर (स्टेट हैंगर) पर आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में दी। उन्होंने बताया कि में इस यात्रा में मप्र को 11 हजार 119 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे पूर्व भी जर्मनी, जापान और यूके आदि की यात्रा के दौरान वहां से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए बड़े प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में निरंतर देश-विदेश से आ रहे निवेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में सहायक होंगे। यह अत्यंत आनंद का विषय है कि मध्यप्रदेश वैश्विक निवेश का केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति की जिंदगी बदलना आवश्यक है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। गरीब, युवा, महिला,किसान सभी वर्गो को साथ लेकर विरासत सहेजने से लेकर विकास की गति बढ़ाने का दृढ़ संकल्प है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित रहने को कहा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री मोदी अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने अपने ग्यारह वर्ष के कार्यकाल में सात बार दुबई की यात्रा कर दो तरफा व्यापारिक और औद्योगिक साझेदारी को बढ़ाने का कार्य किया है। दुबई एक लघु विश्व की तरह है। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री की नीतियों का अनुसरण करते हुए उद्योग एवं व्यापार वर्ष 2025 में देश-विदेश से निवेश लाने के प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में दुबई और स्पेन की यात्रा महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री के संकल्प को पूर्ण करने के लिए इस यात्रा को सार्थक बनाने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का एक-एक निर्णय विश्व में भारत की साख बढ़ाने का कार्य कर रहा है।

मणिपुर में 76 करोड़ की हेराइन और मेथ की गोलियां बरामद

एजेंसी

जिरीबाम (मणिपुर)। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए संयुक्त नदी गश्ती अभियान में करीब 76 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन और मेथ की गोलियां जब्त की गई हैं। अभियान के दौरान एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। अभियान से जुड़े अधिकारियों के अनुसार असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की संयुक्त टीम ने चौधरीखाल और सावोमफाई के बीच बहने वाली बाराक नदी पर गश्त शुरू की। गश्ती के दौरान एक संदिग्ध नाव को नदी से गुजरते देखा गया। जवानों द्वारा रोके जाने पर नाविक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछा कर नाव को रोक लिया गया। तलाशी लेने पर उसमें से 616 साबुनदानी बरामद की गई, जिनमें गई हेरोइन रखी हुई थी। पुलिस ने नाव से होरोईन के साथ-साथ 50 हजार मेथ की गोलियां भी बरामद की है। पुलिस ने अभियान के दौरान एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान असम के सिलचर निवासी के रूप में हुई है। अधिकारियों के मुताबिक, जब्त किए गए मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 76 करोड़ रुपये आंकी गई है। आशंका है कि ये ड्रग्स अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से लाकर मणिपुर की नदियों के जरिए तस्करी की जा रही थी। हाल के महीनों में यह उत्तर-पूर्व भारत में मादक पदार्थों की सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक मानी जा रही है।

प्राइमरी मार्केट में इस सप्ताह 10 आईपीओ की लॉन्चिंग, 3 शेयरों की होगी लिस्टिंग

एजेंसी

नई दिल्ली। सोमवार से शुरू हो रहे कारोबारी सप्ताह के दौरान प्राइमरी मार्केट में काफी हलचल रहने वाली है। इस सप्ताह 10 कंपनियां अपने आईपीओ को लांच कर रही हैं। इनमें से 5 आईपीओ मेनबोर्ड सेगमेंट के हैं, जबकि शेष 5 आईपीओ एसएमई सेगमेंट के हैं। इसके अलावा तीन कंपनियों के शेयर लिस्टिंग के जरिए अगले सप्ताह स्टॉक मार्केट में अपने कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन 21 जुलाई को ही सैवी इंफ्रा का 69.98 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। इस आईपीओ में 23 जुलाई तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ के तहत 114 रुपये से लेकर 120 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1,200 शेयर का है। कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 24 जुलाई को किया जाएगा। इसके बाद 28 जुलाई को एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग होगी। इसी दिन स्वस्तिका कैसल का 14.07 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। इस आईपीओ में भी 23 जुलाई तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ के तहत 65 रुपये प्रति शेयर का भाव तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 2,000 शेयर का है। कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 24 जुलाई को किया जाएगा। इसके बाद 28 जुलाई को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग होगी। सोमवार को ही प्रॉपशेयर टिटैनिया का 473 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। इस आईपीओ में 25 जुलाई तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ के तहत 10 लाख रुपये से लेकर 10.60 लाख रुपये प्रति यूनिट का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1 यूनिट का है। इस इनवेस्टमेंट ट्रस्ट की लिस्टिंग 4 अगस्त को बीएसई पर होगी। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन 22 जुलाई को मोनार्क सर्वेयर्स का 93.75 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। इस आईपीओ में 24 जुलाई तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ के तहत 237 रुपये से लेकर 250 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 600 शेयर का है। कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 25 जुलाई को किया जाएगा। इसके बाद 29 जुलाई को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग होगी। इसके अगले दिन 23 जुलाई को जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का 460.43 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। इस आईपीओ में 25 जुलाई तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ के तहत 225 रुपये से लेकर 237 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 63 शेयर का है। कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 28 जुलाई को किया जाएगा। इसके बाद 30 जुलाई को बीएसई और एनएसई पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। इसी दिन इंडीक्यूब स्पेसेज का 700 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। इस आईपीओ में 25 जुलाई तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ के तहत 225 रुपये से लेकर 237 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि इसका लॉट साइज भी 63 शेयर का ही है। कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 28 जुलाई को किया जाएगा। इसके बाद 30 जुलाई को बीएसई और एनएसई पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। इन दोनों आईपीओ के अलावा इसी दिन टीएससी इंडिया का 25.89 करोड़ रुपये का आईपीओ भी सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। इस आईपीओ में भी 25 जुलाई तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ के तहत 68 रुपये से लेकर 70 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 2,000 शेयर का है। कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 28 जुलाई को किया जाएगा।

'बिग बॉस 16' में टीना दत्ता से दिन-रात लड़ने वाली श्रीजीता डे आजकल कहां हैं? जानें उनके बारे में

रियलिटी शो 'बिग बॉस' के सभी सीजन में जो सबसे पॉपुलर सीजन रहे हैं उनमें 'बिग बॉस 16' भी शामिल था. कहते हैं कि वो सीजन दर्शकों को इतना पसंद आया कि उसे एक महीना आगे बढ़ा दिया गया था. उस सीजन में कई बड़े सितारों ने हिस्सा लिया था जिनमें दो टीवी एक्ट्रेसेस टीना दत्ता और श्रीजिता डे भी बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थीं. पूरे शो में टीना और श्रीजिता का पंगा देखने को मिला लेकिन अब दोनों अपनी-अपनी लाइफ जी रही हैं. यहां बात श्रीजिता डे की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वो अपना 36वां बर्थडे मना रही हैं.

19 जुलाई 1989 को वेस्ट बंगाल के हल्दिया में जन्मीं श्रीजिता डे ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एकता कपूर के 'कसौटी जिंदगी की' से की थी. इसी साल उन्होंने एकता का दूसरा सीरियल 'करम अपना अपना' किया. 2008 में श्रीजिता ने पहली बॉलीवुड फिल्म टशन की थी और उसी साल उन्हें बतौर लीड एक्ट्रेस 'अन्नू की हो गई वाह भई वाह' में काम मिला. यहीं से श्रीजिता का करियर ग्राफ ऊपर चढ़ा, इसके बाद उनका करियर कैसा रहा और आजकल वो क्या कर रही हैं, आइए बताते हैं.

श्रीजिता के हिट टीवी सीरियल

2012 में श्रीजिता का सबसे कामयाब शो उतरन था. उस शो में तपस्या (रश्मि देसाई) और इच्छा (टीना दत्ता) लीड एक्ट्रेस थीं, और सीरियल 20 साल आगे बढ़ा था जिसमें, श्रीजिता ने तपस्या की बेटी का रोल प्ले किया था. वहीं इच्छा की बेटी टीना दत्ता ही बनी थीं, उन्होंने डबल रोल प्ले किया था.

श्रीजिता को इस सीरियल की वजह से घर-घर में पहचान मिली थी.इसके बाद श्रीजिता ने 'तुम्ही हो बंदु सखा तुम्ही', 'पिया रंगरेज', 'कोई लौट के आया है' और 'लव का द एंड' जैसे शोज टीवी पर आए और सभी हिट रहे. श्रीजिता 'सावधान इंडिया', 'श्श्श्शज्‍ कोई है', 'ऐ जिंदगी' और 'महिमा शनी देव की' जैसे शोज भी किए. 2022 से 2023 में बिग बॉस 16 आया, जिसमें श्रीजिता दमदार कंटेस्टेंट्स के तौर पर नजर आई थीं.

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' की शूटिंग के बीच बिगड़ी परिणीति चोपड़ा की सास की तबीयत, जाने कैसा है हाल

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' की तीसरा सीजन कुछ वक्त पहले ही शुरू हुआ है. शो में कई सारे कलाकार भी शामिल हो चुके हैं. हालांकि, हाल ही में शो को शूटिंग के दौरान रोकना पड़ गया. दरअसल, बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की सास की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद से शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ गया. जल्द से जल्द एक्ट्रेस की सास को अस्पताल में भर्ती

करवाया गया है.18 जुलाई को 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के नए एपिसोड की शूटिंग हो रही थी.

जिसमें परिणीति चोपड़ा अपने पति आम आदमी पार्टी (AAP) के युवा नेता राघव चड्ढा के साथ शूटिंग कर रही थी. शो की शूटिंग के दौरान उनकी मां भी सेट पर ही मौजूद थीं. सेट पर मौजूद सूत्रों ने दी जानकारी के मुताबिक, शूटिंग के दौरान अचानक परिणीति की सास की तबीयत बिगड़ने लगी और उनके सिर में तेज दर्द होने लगा था. जिसके बाद से उन्हें नजदीक के ही अस्पताल ले जाया गया.

शेड्यूल हुआ कैंसिल

मां की तबीयत बिगड़ने के वक्त एक्ट्रेस अपनी मां के साथ ही थीं. हालांकि, इस मामले को लेकर परिणीति चोपड़ा और 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के मेकर्स ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. इसके चलते दिन का पूरा शेड्यूल कैंसिल कर दिया गया है. सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है और उनकी हालत को बेहतर बताया है.

शो में आने वाले थे

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने साल 2023 में शादी रचाई थी. हालांकि, शादी के इतने वक्त के बाद से इस कपल को 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' पर देखना उनके फैंस के लिए काफी कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला था. हालांकि, मां की तबीयत की वजह से शूटिंग को बीच में रोक दिया गया है. अब इस एपिसोड को दोबारा कब शेड्यूल किया जाएगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है.

तारक मेहता... शो में हो रही दयाबेन की वापसी? 'सोनू' ने बता दिया सच

पिछले 17 सालों से पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैंस का मनोरंजन कर रहा है. इस टीवी शो के साथ लोगों की बचपन की ढेर सारी यादें जुड़ी हैं. ये उन चुनिंदा शोज में से एक है जो खुद तो इतना हिट है ही साथ ही इस शो के सारे किरदार भी काफी हिट रहे हैं. लेकिन शो में जो किरदार लोगों का सबसे ज्यादा चहेता रहा है वो है दयाबेन का किरदार. पिछले काफी समय से तो दयाबेन को आपने शो में नहीं देखा होगा लेकिन इसके बाद भी वे शो की जान हैं. काफी समय से उन्हें शो में वापिस लाने की डिमांड की जा रही है. अब शो में सोनू का रोल प्ले कर पॉपुलर हुई एक्ट्रेस निधि भानुशाली ने इसपर रिएक्ट किया है.

निधि भानुशाली ने क्या कहा ?

एक्ट्रेस निधि भानुशाली ने हाल ही में शो के बारे में बातें की. उन्होंने दयाबेन के रोल में दिशा वकानी की वापसी पर भी अपने विचार रखे. एक्टर ने कहा- मैं ईमानदारी से कहूं कि हम और आप इस बारे में बात करने वाले कोई नहीं हैं. ये पूरी तरह से उनका जीवन है और उनकी यात्रा है. और उन्हें क्या करना है इसका निर्णय भी वे खुद ही लेंगी.

लेकिन हम सभी जरूर ये चाहते हैं कि वे शो में फिर से वापसी करें. लेकिन ये सबसे जरूरी है कि हम उनके डिसीजन की कद्र करें और बिना किसी शर्त के उनका समर्थन करें. साथ ही उनके बेहतर भविष्य की कामना करें. उन्होंने इस शो को और समाज को जो कुछ भी दिया है हम उसके आभारी हैं.

आ चुके हैं 4000 से ज्यादा एपिसोड्स

शो की बात करें तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो साल 2008 में शुरू हुआ था. तब से लेकर अब तक इस शो को 17 साल का वक्त हो गया है और इसके 4310 एपिसोड्स अबतक ऑन एयर हो चुके हैं. ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और शायद ही इससे ज्यादा एपिसोड्स किसी सीरियल के आए होंगे. शो में दिशा वकानी की बात करें तो वे शुरुआत के 10 साल इस शो का हिस्सा थीं. लेकिन इसके बाद वे पर्सनल कारणों से शो से अलग हो गईं और अब पूरे 8 साल बाद उनकी वापसी की खबरों ने एक बार फिर से फैंस के बीच उत्साह जगा दिया है.

जिस दिन रिलीज हुई सलमान-काजोल की ये फिल्म, उसी दिन सोहेल खान ने मंदिर में की थी शादी

सलमान खान की तरह उनके दोनों छोटे भाईयों सोहेल खान और अरबाज खान को सक्सेस और लोकप्रियता नहीं मिल पाई. सलमान की तरह ही अरबाज और सोहेल ने भी बतौर एक्टर काम किया, हालांकि एक्टिंग में उनका करियर फ्लॉप रहा. हालांकि दोनों की पर्सनल लाइफ की बात करें तो सोहेल और अरबाज इस मामले में सलमान की तरह नहीं रहे. दोनों ने शादी करके घर बसा लिया था.अरबाज खान ने पहले एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा से शादी की थी. हालांकि 19 साल के बाद दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे. इसके बाद अभिनेता ने दूसरी शादी शूरा खान से की. वहीं सोहेल ने सीमा सजदेह से शादी की थी. लेकिन, सोहेल और सीमा का भी तलाक हो गया था. हालांकि दोनों तलाक से पहले एक लंबे अरसे तक साथ रहे. कपल ने प्यार की खातिर धर्म की दीवार भी तोड़ दी थी. अलग-अलग धर्मों के चलते उन्हें भागकर शादी

करनी पड़ी थी.

जिस दिन रिलीज हुई ये फिल्म, उसी दिन की शादी

सोहेल और सीमा ने उस दिन शादी की थी जिस दिन सोहेल की फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' रिलीज हुई थी. साल 1998 में ये पिक्चर 27 मार्च को रिलीज हुई थी. इसमें सलमान खान, अरबाज खान, काजोल, धर्मेंद्र, अंजला जावेरी, किरण कुमार और प्राण जैसे कलाकार नजर आए थे. वहीं सोहेल ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था.सोहेल को पहली नजर में ही दिल्ली की रहने वाली सीमा से प्यार हो गया था. लेकिन, सीमा की फैमिली सोहेल संग उनके रिश्ते के खिलाफ थी. ऐसे में दोनों ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया था. दोनों ने प्यार किया तो डरना क्या की रिलीज वाले दिन ही घर से भागकर मुंबई के एक आर्य समाज मंदिर में शादी करके अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया था. बाद में सीमा की फैमिली मान गई थी. फिर उन्होंने मुस्लिम धर्म के अनुसार भी शादी की थी.

2022 में हो गया था तलाक

शादी के बाद सोहेल और सीमा दो बेटों के पैरेंट्स बने थे. उनके एक बेटे का नाम निर्वाण और एक का नाम योहान हैं. सोहेल और सीमा ने शादी के करीब 24 साल बाद तलाक लेकर अपना रिश्ता खत्म कर लिया था. दोनों का तलाक साल 2022 में हुआ था.

वीरेंद्र सचदेवा ने शिव भक्त कांवड़ियों का पुष्प वर्षा द्वारा हार्दिक अभिनंदन

दिव्य दिल्ली

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज शाहदरा में दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर शिव कांवड़ सेवा समिति द्वारा आयोजित शिविर में दिल्ली अगमान पर शिव भक्त कांवड़ियों का पुष्प वर्षा द्वारा हार्दिक अभिनंदन किया। इस मौके पर विधायक श्री संजय गोयल, जिला अध्यक्ष श्री दीपक गाबा और निगम पार्षद श्री पंकज लूथरा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। वीरेंद्र सचदेवा ने इस मौके पर ना सिर्फ. कांवड़ियों की सेवा में की जाने वाली बंदोबस्त का निरीक्षण किया बल्कि वहाँ उपस्थिति सभी सेवकों से किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इसके लिए सबको आश्वस्त किया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस हर साल

कांवड़ियों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बंदोबस्त किया जाता रहा है, लेकिन इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार है और उसने कांवड़ियों के लिए पिछली सरकारों से बेहतर बंदोबस्त किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांवड़ियों की सेवा में भाजपा पहले भी थी क्योंकि हमारे लिए यह किसी जन आस्था और संस्कृति का महोत्सव है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस बार कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए अभूतपूर्व तैयारियां की हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा ना हो उसके लिए पहली बार राजधानी में 17 स्वागत द्वार बनाये गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शिव भक्तों की सुरक्षा और सुव्यवस्था ही हमारी पहली प्राथमिकता है।

सोलन में बारिश का कहर जारी

दिव्य दिल्ली : अमरप्रीत सिंह (सोलन)

हिमाचल प्रदेश में बीते दो दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। सोलन जिला में अब तक बारिश से करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पीडब्ल्यूडी विभाग सोलन के एसई अजय शर्मा ने बताया कि दो दिनों से लगातार बारिश जारी है ऐसे में रोड बंद होने के समाचार भी आ रहे हैं। अभी तक जिला में 19 रोड बंद है उन्होंने कहा कि आज 18 रोड़ खोल दिए जाएंगे वहीं एक अन्य रोड को कल तक खोलने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सभी एसडीओ फील्ड स्टाफ को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से जिला में 30 जेसीबी लगाई गई है जिसमें 10 विभाग की है और 20 हायर की गई है। इसी के साथ टिप्पर और डोजर समेत कुल 44 मशीन जिला में लगी हुई है।

न्यूज फ्लैश

योगेंद्र कुमार ने वन महोत्सव के शुभ अवसर पर वृक्ष का पौधा रोपण किया

दिव्य दिल्ली : दिल्ली

22/7/2025 को योगेंद्र कुमार सह अधीक्षक जेल एवं मानद पशु कल्याण प्रतिनिधि (भारतीय पशु कल्याण बोर्ड) ने इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक इनर व्हील क्लब ने साथ मिलकर गवर्मेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 3 तिलक नगर में वन महोत्सव के शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में फलदार एवं ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष का पौधा रोपण किया था बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया इस अवसर पर योगेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों से निवेदन किया कि जिस विद्यार्थी ने पौधारोपण किया है वो ही उसकी देखभाल करेगा तथा प्रधानाचार्य रेनू सेठी ने भी विद्यार्थियों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया तथा मीरा तलवार अध्यक्ष ने भी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने जन्मदिन पर एक पौधा रोपण जरूर करे । शुचि सूद सचिव, डॉ परमजीत छाबड़ा संयुक्त सचिव ,रीता सिंहा कोषाध्यक्ष ,मिन्नी गोसाईं आईएसओ ,सुशीला गुप्ता सदस्य ने भी बच्चों जागरूक किया ।

एनडीआरएफ के जवानों ने जल शक्ति विभाग के एक पंप ऑपरेटर को सुरक्षित निकाला

दिव्य दिल्ली :विनय महाजन (नूरपुर)

उपमंडल नूरपुर में भारी बारिश के कारण जब्बर खड्ड में आई भारी बाढ़ के कारण नूरपुर शहर के साथ लगते डिफेंस रोड के निकट जब्बर खड्ड किनारे जल शक्ति विभाग की एक वाटर सप्लाई स्कीम पर एक पंप ऑपरेटर बाढ़ में फंस गया जिसे प्रशासन ने एनडीआरएफ की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया।उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण नूरपुर के डिफेंस रोड साथ बहती जब्बर खड्ड में भारी बाढ़ आ गई जिससे जब्बर खड्ड साथ लगती वाटर सप्लाई स्कीम पर कार्यरत एक पंप ऑपरेटर फंस गया । इस बारे संबंधित विभाग ने सूचना मिलते ही नूरपुर प्रशासन को सूचित किया।एस डीएम नूरपुर अरुण शर्मा ने बताया कि पंप ऑपरेटर को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ को सूचना दी गई और एनडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद उक्त पंप ऑपरेटर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण कोट पलाहड़ी सड़क मार्ग बंद हो गया था जिसकी सूचना मिलने पर सड़क मार्ग को यातायात के लिए खुलवा लिया गया है और भारी बारिश के कारण खज्जियां में एक घर खतरे में आ गया था उसकी सूचना मिलने पर वहां पानी की निकासी करवाई गई तथा फिलहाल घर को सुरक्षित किया गया।

नेशनल अकाली दल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर करेगा कार्यक्रम

दिव्य दिल्ली

नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा का कहना है कि जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर कर-के भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है इसको लेकर सभी को अपने देश की सेना व सरकार पर गर्व है। पम्मा ने बताया 27 जुलाई को ऑपरेशन संदूर की सफलता को लेकर एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें डॉक्टर, वकील, समाजसेवी व व्यापारी उपस्थित होंगे और उन्हें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की शपथ दिलाई जाएगी क्योंकि समय-समय पर लोगों को देशभक्ति से जोड़ना जरूरी है। पम्मा ने कहा कि वह समय-समय पर स्कूलों में जाकर बच्चों को देश के प्रति जागरूक करेंगे और उन्हें ऑनलाइन गेम में ना खेलने की भी शपथ दिलाएंगे। इस अवसर पर नेशनल अकाली दल महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना धवन ने बताया एक दशक से एंग्री मैन का खिताब परमजीत सिंह पम्मा जी नाम पर होने पर समारोह किया जाएगा साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में देश व समाज के हित में कार्य करने वालों को एन ए डी देश रतन 2025 अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।

फॉल आर्मी वर्म के तेज प्रकोप को लेकर कृषि मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न

नॉर्थ जोन, विशेषकर कांगड़ा जिला के कई क्षेत्रों में फॉल आर्मी वर्म का तीव्र और व्यापक प्रकोप देखा गया है

दिव्य दिल्ली : ऊषा जरियाल (जवाली)

उपमंडल जवाली के अंतर्गत कृषि मंत्री की चौधरी चन्द्र कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को शहीद सुरेंद्र सिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जावली में मक्का फसल पर बढ़ते फॉल आर्मी वर्म प्रकोप की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नॉर्थ जोन के अतिरिक्त कृषि निदेशक डॉ. राहुल कटोच, चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति डॉ. नवीन कुमार, उप कृषि निदेशक डॉ कुलदीप धीमान उपस्थित रहे। बैठक में डॉ. राहुल कटोच द्वारा अवगत कराया गया कि नॉर्थ जोन, विशेषकर कांगड़ा जिला के कई क्षेत्रों में फॉल आर्मी वर्म का तीव्र और व्यापक प्रकोप देखा गया है। स्थिति चुनौतीपूर्ण होते हुए भी विभाग द्वारा समय रहते प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण संभव हुआ है। बैठक में माननीय कृषि मंत्री द्वारा सुझाव दिया गया कि प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों पर आधारित रोकथाम के उपायों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि कीट नियंत्रण में कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो सके। वहीं विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि सघन और नियमित निगरानी ही संक्रमण की समय रहते पहचान और नियंत्रण की कुंजी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विकास खण्ड स्तर के कृषि अधिकारियों की फील्ड टीमें गांव स्तर पर सक्रिय निगरानी कर रही हैं। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग की राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला, पालमपुर के अधिकारी तथा कृषि वैज्ञानिकों की एक जिला स्तरीय टीम बनाई गई है जो कि अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में नियमित सर्वेक्षण और निगरानी कर रहे हैं।

कृषि मंत्री प्रोफेसर चन्द्र कुमार ने किसानों से अपील की है कि वे फसलों की नियमित निगरानी करें, और किसी भी कीट प्रकोप की सूचना तुरंत स्थानीय कृषि अधिकारियों को दें। विभाग की टीमें युद्धस्तर पर कीट नियंत्रण के कार्य में जुटी हैं।

प्रकोप की गंभीरता को देखते हुए विभाग में अनुशंसित रसायन 'कोरेजन' पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसे किसान ब्लॉक स्तर कृषि विभाग के कार्यालय से पर सब्सिडी दरों पर प्राप्त कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने कृषि अधिकारियों को आदेश दिए कि दूसरे राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों से भी इस कीट के नियंत्रण के लिए सम्पर्क किया जाए और उनसे भी यह चर्चा की जाए की उनके राज्य में इस कीट के नियंत्रण के लिए क्या प्रयास किये जा रहे है ताकि उनके द्वारा किये जा रहे प्रयासों को भी हिमाचल में अमल में लाया जाये और इस कीट का सफल नियंत्रण किया जाए क उन्होंने इस कीट के प्रकोप के साप्ताहिक आधार पर निगरानी रिपोर्ट मांगी है

सुनील कुमार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बने

दिव्य दिल्ली : करूनीत रंधावा (पठानकोट)

राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावधस की बैठक जिला युवा अध्यक्ष हरीश हैप्पी और उपाध्यक्ष जसपाल सोनू के नेतृत्व में हुई, जिसमें पंजाब अध्यक्ष अमित रंधावा विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर अमित रंधावा ने सुनील कुमार को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का ज़िला अध्यक्ष नियुक्त किया और उन्हें अपनी कमेटी बनाने का अधिकार दिया। इस अवसर पर अमित रंधावा ने कहा कि हमारे संगठन का काम दबे-कुचले लोगों पर हो रहे अत्याचार को रोकना है। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन हर उस व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा जिस पर अत्याचार होगा और उसे न्याय दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि चाहे पंजाब की सरकार हो या केंद्र की, दोनों ही सरकारें गरीब जनता का शोषण कर रही हैं।

ठेकेदारी प्रथा चलाकर, दोनों ही सरकारें कम वेतन पर काम करवाकर गरीब जनता पर अत्याचार कर रही हैं, जिसके खिलाफ उन्हें जल्द ही अपने ही विरोध का सामना करना पड़ेगा। संगठन शोषण का शिकार हो रहे कर्मचारियों के पक्ष में आवाज उठाएगा और खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन पूरे समाज को साथ लेकर चलेगा ताकि अखंड भारत की स्थापना हो सके। इस अवसर पर पंजाब महासचिव कमल गिल, विकास सहोता, रोहित चीते, सरपंच गवर्धन दास आदि उपस्थित थे।

45.1 ग्राम हेरोइन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

जिला पठानकोट पुलिस पठानकोट में नशे के खात्मे के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में, गत दिन पठानकोट पुलिस ने अबरोल नगर पुल पर एक नाका लगाया था और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की गहन तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान, पैदल आ रहे दो लोगों को पुलिस ने रोककर तलाशी ली तो उनके पास से 45.1 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। हेरोइन बरामद होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस एसपी मनोज ठाकुर ने बताया कि कल उन्होंने एक नाका लगाया था और इसी दौरान जब दो राहगीरों को रोका गया, तो उनके पास से 45.1 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। उन्होंने बताया कि जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो उनमें से एक ने कबूल किया कि शहर में 2025 में हुई सभी झपटमारी की घटनाओं को उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर अंजाम दिया था, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने बताया कि जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो भी बरामदगी होगी, उसे आपके माध्यम से जनता के सामने लाया जाएगा। आरोपियों की पहचान एंथनी उर्फ साहिल पुत्र लकी सराय मोहल्ला पठानकोट और दूसरे युवक ने अपना नाम विशाल कुमार उर्फ विशु पुत्र विजय कुमार निवासी नजदीक किराना स्टोर सुंदर नगर पठानकोट बताया। चेकिंग के दौरान वह खाई में कूद गया। खाई में पत्थर होने के कारण उसके पैर में चोट लग गई। चेकिंग के दौरान एंथनी उर्फ साहिल से 14 ग्राम हेरोइन मोम के लिफाफे सहित बरामद हुई और विशाल कुमार उर्फ विश से 31 ग्राम 12 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई। जिस पर उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ मुकदमा नंबर 106 दिनांक 19.07.2025 सुलभ 21/22-61-85 एनडीपीएस एक्ट, 111 बीएनएस थाना डिवीजन 1 में दर्ज किया गया और जांच जारी है।

ऊपर से ट्रेन निकलती रही नीचे पुल की सेफ्टी वाल बाढ़ में बह गए

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

भारी बारिश के चलते पठानकोट एयरपोर्ट को जाने वाला रास्ता पूरी तरह से हुआ की क्षतिग्रस्त मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक बलिंदर राजन तथा उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी हर वर्ष की भांति इस साल भी भारी वर्ष के चलते पठानकोट ढांगू पीर माजरा सड़क निर्माण सड़क पर हर वर्ष बरसात के दिनों में रेलवे पुल जो दिल्ली-पठानकोट-जम्मू रेल मार्ग है जिसमें करीब 100 से ज्यादा रेल गाड़ियां गुजरती है उस पुल पर बरसातों के दौरान हमेशा खतरा बना रहता है। इस वर्ष भी आज पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के चलते आज फिर से वही मंजर देखने को मिला। रेलवे ब्रिज के निर्माण में लगी हुई एक मशीन चक्की के तेज प्रभाव में बह गई तथा ढांगू माजरा, ढांगू पीर सड़क मार्ग जो कि दो पंचायत के लिए एकमात्र ही रास्ता है वह भी सुरक्षा की दृष्टि से आज विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है। इसका ज्याजा लेने के लिए आज स्थानीय विधायक बलिंदर राजन उनके साथ एसडीएम डॉक्टर सुंदर ठाकुर, तहसीलदार लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी, स्थानीय पुलिस अधिकारी तथा रेलवे के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिसके तहत उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद इस रास्ते को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 3 साल पहले भी यह रास्ता बंद होने के कारण मिलिट्री अस्पताल के बीच में से रास्ता निकाल कर स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए इसे खोल दिया गया था। आज भी मौके पर डीसी कांगड़ा से बात की तथा बच्चों स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए जो इसी रास्ते से स्कूल में पढ़ने जाते हैं उसकी पढ़ाई बाधित न हो जिसके चलते वैकल्प रास्ता खोलने की मांग की है। याद रहे कि यह कई सालों से हर वर्ष तेज बारिश के चलते चक्की दरिया में यह हालात आसामान्य हो ही जाते हैं।

इसका मुख्य कारण है वहां चक्की में होता अंधाधुंध खनन है जो लगातार चक्की दरिया में लाखों करोड़ों की अवैध खनन करके इसमें खनन सामग्री निकाली जा रही है परंतु प्रशासन तथा पुलिस की मिली भक्ति के चलते यह सब जोरों पर चला हुआ है चलो अब देखते हैं कितने दिन लोगों को इसमें राहत मिलेगी

जीनियस ग्लोबल स्कूल के छात्र ध्रुव का पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय बनिया देवी में चयन

दिव्य दिल्ली : अमरप्रीत सिंह (सोलन)

सोलन जिले के प्रतिभाशाली छात्र ध्रुव ने पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय बनिया देवी में कक्षा 6 के लिए 2025-26 सत्र में अस्थाई रूप से चयनित होकर अपने स्कूल और जिले का नाम रोशन किया है। ध्रुव वर्तमान में जीनियस स्कूल में अध्ययनरत हैं। हर साल हजारों छात्र इस प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा में भाग लेते हैं, लेकिन ध्रुव ने अपनी मेहनत और लगन से यह स्थान हासिल किया। ध्रुव मूल रूप से सोलन का ही निवासी है। उनकी इस सफलता से जीनियस स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई है। स्कूल की डायरेक्टर नीति शर्मा ने ध्रुव की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्कूल के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने ध्रुव को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दीं।

गुल्लक से पैसे निकालकर उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाई

दिव्य दिल्ली : शशि भूषण (धर्मशाला)

धर्मशाला के समीप स्थित शिल्ला चौक के रहने वाले और सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले 13 वर्षीय छात्र प्रथम पुरी ने इंसानियत और संवेदनशीलता की एक मिसाल पेश की है। प्रथम पुरी लंबे समय से प्लेस्टेशन फाइव गेमिंग कंसोल खरीदने के लिए अपनी गुल्लक में पैसे जमा कर रहा था।

नूरपुर क्षेत्र में भारी बारिश से विद्युत खंभों को नुकसान, कई पंचायतों में बिजली आपूर्ति ठप

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर क्षेत्र में हुई भारी बारिश से जब्बर खड्ड में आये पानी से खड्ड के समीप खेतों में 33 केवी के खंभों को पानी से भारी नुकसान हुआ। इस मामले में 3 पोल स्ट्रक्चर के पोल और 11 के वी पोल दोनों के कुछ खम्बे पानी मे बह गये ओर साथ कुछ तारो को भी बहा ले गए। इस मामले मे विभाग के सहायक अभियंता आशीष धीमान के अनुसार थपकोर सब स्टेशन से अल्टरनेटिव व्यवस्था बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।इसके चलते जसूर के समीप अन्य क्षेत्रों कंडवाल,खन्नी, कमनाला, बोड़, राजा के बाग सहित अनेक पंचायतों में विधुत आपूर्ति गत आधी रात से बाधित है'

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397